



मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा

पंचम सत्र

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी, 2015

(30 माघ, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 5]

[अंक- 2]

मध्यप्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी, 2015

(30 माघ, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन् शर्मा) पीठासीन हुए.}

निधन का उल्लेख

1. श्री रामेश्वर ठाकुर, पूर्व राज्यपाल,
2. डॉ. मालती मौर्य, पूर्व विधान सभा सदस्य,
3. श्री शंकरलाल साबू, पूर्व विधान सभा सदस्य,
4. कुंवर अशोक वीर विक्रम सिंह, पूर्व विधान सभा सदस्य,
5. श्री आर.के. लक्ष्मण, सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट,
6. धार जिले में यात्री बस खाई में गिरने से मृत व्यक्ति.

निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है कि मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर का 15 जनवरी, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यगण डॉ. मालती मौर्य का 14 जनवरी, श्री शंकरलाल साबू का 20 जनवरी, 2015, ~~द्वारा~~ अशोक वीर विक्रम सिंह का 19 दिसम्बर, 2014 एवं सुप्रसिद्ध काटूर्निस्ट श्री आर.के. लक्ष्मण का 26 जनवरी, 2015 को निधन हो गया है।

श्री रामेश्वर ठाकुर का जन्म 28 जुलाई, 1927 को ग्राम ठाकुर गंगटी, जिला मोड्डा (झारखण्ड) में हुआ था। आपने 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और जेल में निरूद्ध रहे। आप इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एवं राजीव गांधी सदभावना अवार्ड के संस्थापक सचिव एवं अनेक राजनैतिक, सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहे। आप 1984 से 1990 एवं 1990 से 1996 में राज्यसभा के सदस्य और जून, 1991 से दिसम्बर, 1994 तक भारत सरकार में वित्त (राजस्व), ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री रहे। आप बिहार एवं उत्तरप्रदेश राज्य योजना आयोग के सदस्य भी रहे। श्री ठाकुर ने उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं मध्यप्रदेश के राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किया।

आपके निधन से देश ने एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक, वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं कर्मठ समाजसेवी खो दिया है।

डॉ.मालती मौर्य का जन्म 2 जुलाई, 1952 को खुरई, जिला सागर में हुआ था। श्रीमती मौर्य ने एक कुशल चिकित्सक के रूप में मानवता की सेवा की। आपने महिलाओं की शिक्षा एवं उनके सामाजिक उत्थान की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किये। आपको मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा 22 सितम्बर, 1989 को “विधान श्री” की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। आपने 1985 से 1990 के दौरान प्रदेश की आठवीं विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से खुरई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

आपके निधन से प्रदेश ने एक लोकप्रिय नेत्री एवं कर्मठ समाजसेवी खो दिया है।

श्री शंकरलाल साबू का जन्म 10 अक्टूबर, 1940 को सीहोर में हुआ था। श्री साबू 1961 से राजनीति से जुड़े और 14 वर्षों तक जिला युवक कांग्रेस सीहोर के अध्यक्ष रहे। आप नगर सुधार न्यास सीहोर और सीहोर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष तथा नगर पालिका के एलडरमेन रहे। आपने पार्टी के विभिन्न आन्दोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई तथा अनेक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्ध रहे। आप साप्ताहिक जनवाहक के संस्थापक संपादक थे। श्री साबू ने 1985 से 1990 के दौरान प्रदेश की आठवीं विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सीहोर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

आपके निधन से प्रदेश के सार्वजनिक जीवन की अपूरणीय क्षति हुई है।

श्री अशोक वीर विक्रम सिंह का जन्म 22 दिसम्बर, 1949 को ग्राम सांटा बुद्धसिंह जिला पन्ना में हुआ था. आप 1990 से 1992 में नौवीं एवं 1998-2003 में ग्यारवीं विधान सभा के सदस्य रहे.

श्री आर.के.लक्ष्मण का जन्म 24 अक्टूबर, 1921 को मैसूर में हुआ था. श्री लक्ष्मण ने लगभग पांच दशक तक अपने तीक्ष्ण और चुटीले कार्टूनों के माध्यम से विषमताओं और विद्रूपताओं को उकेरा. उन्होंने "आम आदमी" के प्रसिद्ध चरित्र को गढ़ा और उसके जरिये वे परिवेश में हो रहे नित नये बदलावों को प्रदर्शित और रेखांकित करते रहे श्री लक्ष्मण को 1984 में रैमन मैगसेस अवार्ड, 2005 में पद्म विभूषण एवं 2012 में पुणे पंडित अवार्ड के साथ ही अन्य कई सम्मानों से विभूषित किया गया था.

आपके निधन से देश ने एक शीर्षस्थ और सिद्धहस्त कार्टूनिस्ट खो दिया है.

दिनांक 16 फरवरी, 2015 को धार जिले के माछलिया घाट में एक यात्री बस के खाईमें गिरने से कई यात्रियों की मृत्यु हो गई एवं अनेक घायल हुए.

यह सदन इस हादसे में मृत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है.

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामेश्वर ठाकुर मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे उनका निधन 15 जनवरी, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यगण डॉ.मालती मोर्य, का 14 जनवरी को, श्री शंकरलाल साबू, का 20 जनवरी, कुंवर अशोक वीर विक्रम सिंह, 19 दिसम्बर 2014, एवं सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के.लक्ष्मण का 26 जनवरी, 2015 को निधन हो गया है मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामेश्वर ठाकुर, पूर्व राज्यपाल, पूर्व विधायक डॉ.मालती मोर्य जी, श्री शंकरलाल साबू जी, संयोग से डॉ. मालती मोर्ड एवं श्री शंकरलाल साबू के साथ हमें विधान सभा में रहने का मौका मिला. श्री अशोक वीर विक्रम

सिंह भी इस सदन में रहे, श्री आर.के.लक्ष्मण, सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट इन सबके निधन से यह महान हस्तियां हमारे बीच से चली गई हैं, इससे प्रदेश को बड़ी क्षति हुई है इसकी पूर्ति हम जल्दी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सबको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं तथा इनके लिये श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं.

श्रीमती शीला त्यागी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री रामेश्वर ठाकुर पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व विधान सभा सदस्यगण डॉ.मालती मौर्य जी,माननीय श्री शंकरलाल साबू जी, माननीय श्री अशोक वीर विक्रम सिंह जी एवं श्री आर.के.लक्ष्मण सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट एवं धार जिले में यात्री बस खाई में गिरने से मृत व्यक्तियों को उनकी आत्मा की शांति के लिये अपनी ओर से तथा बहुजन समाज पार्टी की ओर से सबको श्रद्धासुमन अर्पित करती हूं.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामेश्वर ठाकुर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा एक कुशल प्रशासक थे. वे केन्द्र में मंत्री रहे और यह एक सुखद संयोग है कि हमारे मध्यप्रदेश के माननीय राज्यपाल भी रहे. वे एक बिरले व्यक्ति हैं जिनको यह अवसर मिला, वे कई राज्यों जैसे उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक के राज्यपाल रहे. उन्हें कई अवार्डों से जैसे राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड, इन्दिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन से सम्मानित किया गया. निसंदेह उनके निधन से एक बहुत बड़ी सार्वजनिक जीवन में क्षति हुई है मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

अध्यक्ष महोदय, डा. मालती मौर्य एक प्रेक्टिसिंग डाक्टर थीं. चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय रहीं गरीबों का ईलाज करने में ऐसी मुझे जानकारी है कि गरीबों से वह फीस नहीं लिया करती थी तदोपरांत 1985 से 1990 तक वे विधान सभा की सदस्य भी रहीं. बड़ा अच्छा परफार्मेंस उनका सदन में रहा. उन्हें विधानश्री पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था उनका असमय निधन हुआ इसके लिये हम सबको गहरी संवेदना है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह सदमा वहन करने की शक्ति दे.

अध्यक्ष महोदय, श्री शंकरलाल साबू, एक बहुत ही सरल व्यक्ति थे और मूलतः वे पत्रकार थे उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन में अपना जीवन निचले स्तर से कार्पोरेटर के रूप में शुरू किया विधायक बने और विधायक बनने के साथ-साथ पत्रकारिता से उन्होंने अपना संबंध बनाए रखा और जब वे अक्सर आया करते थे जनवाहक पत्रिका हम लोगों को निःशुल्क पढ़ने को देते थे उसमें अच्छे लेख होते थे उसमें उनके भी निधन से एक सार्वजनिक क्षति हुई है. मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुं. अशोक वीर विक्रम सिंह सदन के दो बार सम्मानित विधायक रहे. सहकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहा करते थे. पन्ना जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा. उनकी पत्नी भी सम्मानित विधायक रहीं हैं. उनके बारे में मैं जानता हूं. निकट से परिचित रहा हूं. आम आदमी से बड़ा उनका निकट का नाता था वे गरीबों की मदद करते थे. उनके न रहने से बड़ी गहरी वेदना हमें हुई है. उनके परिवार को ईश्वर यह सदमा वहन करने की शक्ति दे.

स्वर्गीय आर.के.लक्ष्मण आम आदमी के व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसके चरित्र का सटीक चित्रण करते थे. जब भी टाइम्स आफ इंडिया अखबार हाथ में आता था तो हेडलाइंस पढ़ने के बाद स्वाभाविक तौर पर नजर उनके कार्टून पर जाती थी. हम सबको उनका कार्टून गुदगुदाता था और देश, समाज में क्या हो रहा है इसकी अभिव्यक्ति होती थी. उसका अहसास हमें कराते थे. अनेकों पुरस्कार से सम्मानित हुए. पद्मविभूषण, भारत रत्न के बाद सर्वोच्च अलंकरण है उससे सरकार ने और भारत की जनता ने उन्हें सम्मानित किया. मेगसेसे अवार्ड भी उन्हें मिला था. हमारे बीच नहीं रहे. एक रिक्तता आई है पत्रकारिता के क्षेत्र में और विशेषकर जो लोग कार्टून बनाते हैं अब वैसा कार्टूनिस्ट है नहीं अभी वर्तमान में. उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं.

अध्यक्ष महोदय, धार जिले में जो मछलिया घाट में बस हादसा हुआ बस खाई में नीचे गिरी और कई लोगों की मृत्यु हुई मैं उन आत्माओं की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

अध्यक्ष महोदय – मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं. अब सदन दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेगा.

(सदन में दिवंगतों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया.)

ओम शांति..दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित.

(10.40 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित की गई.)

(10.40 बजे से 5 मिनट का अंतराल)

10.51 बजे {अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन् शर्मा) पीठासीन हुए.}

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न क्रमांक -1.....

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न काल हो जाने दीजिये, आप ही लोगों के प्रश्न होते हैं।

नेता प्रतिपक्ष :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ व्यवस्था के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है।

श्री सत्यदेव कटारे :- अध्यक्ष महोदय, हमें मालूम है इसीलिये हम उसको व्यवस्था का प्रश्न कहकर नहीं उठा रहे हैं। परन्तु कल हम यहां पर बन्दे मातरम् करने से चुक गये, कल बन्दे मातरम् नहीं हुआ। दूसरा कल बिना कार्यमंत्रणा के सदन कैसे चलने लगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप कितने बजे आये थे।

श्री विश्वास सारंग :- कल वन्दे मातरम् हुआ है। (व्यवधान) आप थे नहीं।

श्री कमलेश्वर पटेल :- इनकी मानसिकता में वन्दे मातरम् नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- श्री सुन्दरलाल तिवारी की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं आयेगी।

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- xxx

अध्यक्ष महोदय :- आपकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं आ रही है। श्री कुंवर सिंह टेकाम अपना प्रश्न करें। आप कृपा करके प्रश्न काल होने दें।

श्री कुंवर सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- श्री तिवारी जी आप कृपा करके बैठ जायें, प्रश्नकाल हो जाने दें। तिवारी जी यह बात ठीक नहीं इस तरह से आप पूरे सदन को बाधित करते हैं। यह बिल्कुल उचित नहीं है। आपकी बात रिकार्ड में नहीं आ रही है। आप कृपा करके बैठ जायें, श्री टेकाम अपना प्रश्न करें। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्न काल चलने दें, ताकि सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकें।

श्री रामनिवास रावत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो इसलिये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इनकी बातें अच्छी लग रही हैं।

श्री सुदर्शन गुप्ता :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भाजपा के अन्दर की बात इनको कैसे मालूम। आपको सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने धुतकार दिया, भगा दिया (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्नकाल होने देना चाहते हैं या नहीं, आप कृपया प्रश्न काल होने दें, आप कृपया माननीय सदस्य को कृपा अपना प्रश्न करने दें, यह बात ठीक नहीं है, आप लोग कृपा करके बैठ जायें, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है आप लोग जानते हैं। कुंवर सिंह टेकाम अपना प्रश्न करें।

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- xxx

श्री विश्वास सारंग :- लूटा तो रीवा में था।

XXX- आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय—श्री कुंवर सिंह टेकाम अपना प्रश्न करें. (व्यवधान)

श्री लाल सिंह आर्य—(XX) (व्यवधान)

श्री विश्वास सारंग—(XX) (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—(XXX)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—लुट तो पूरी कांग्रेस गई.(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य—विधान सभा से गई लोकसभा से गई (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप लोग प्रश्नकाल चलने देना चाहते हैं कि नहीं (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—एक भी जगह नाम नहीं है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप कृपा करके यह बतायें कि आप प्रश्नकाल चलने देना चाहते हैं कि नहीं चलने देना चाहते हैं, यह बात बिलकुल उचित नहीं है कि एक सदस्य विधान सभा की कार्यवाही को बाधित करे, यह बिलकुल उचित नहीं है, कृपा करके आप बैठ जायें, सभी लोग बैठ जायें (व्यवधान) मेरा माननीय तिवारी जी से अनुरोध है कि आप कृपा करके कार्यवाही चलने दें और इस महत्वपूर्ण समय को जाया न करें. आप माइक को बंद ही रहने दें, कृपा करके बैठ जाइये.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—(XXX)

श्री विश्वास सारंग—अध्यक्ष महोदय, इनकी कुर्सी बदलवाओ (व्यवधान)

श्री रामेश्वर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, यह बातों से मान ही नहीं सकते हैं.(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—(XXX)

श्री भूपेन्द्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते हैं (व्यवधान)

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय—श्री सुन्दरलाल जी तिवारी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके सदन की कार्यवाही चलने दें, एक सदस्य इस तरह से सदन की कार्यवाही को बाधित करेगा तो बिलकुल खराब बात रहेगी आप कृपा करके इस बात पर ध्यान दें आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप शांति रखें. प्रश्नकाल होने दें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—(XXX)

श्री सुदर्शन गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है इनकी व्यवस्था आप हमेशा कीजिये(व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—यहां व्यापम व्यापम करते रहे लोकसभा में जनता ने फजीहत कर दी लोकसभा में ऐसी धूल चटाई इनको.(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—(XXX)

अध्यक्ष महोदय—तिवारी जी आप बैठ जाइये यह बात बिलकुल ठीक नहीं है तिवारी जी एक अकेले आप बाधित कर रहे हो पूरे सदन को यह हम बिलकुल एलाउ नहीं करेंगे, आप कृपा करके मुझे कोई भी कार्यवाही करने के लिए बाधित नहीं करें(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जायें, मेरा आपसे आदेश नहीं विनम्र निवेदन है आप कृपा करके बैठ जाइये, बैठ जाइये. श्री टेकाम (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—(XXX)

अध्यक्ष महोदय—श्री कुंवर सिंह टेकाम

श्री रामेश्वर शर्मा—यह तरीका बिलकुल उचित नहीं है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप अपने साथी को तो बैठाइये (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—(XXX)

अध्यक्ष महोदय—आप गलत समय बात कर रहे हैं सही समय पर बात करिए, बैठ जाइये, सभी लोग बैठ जायें, कृपया बैठ जायें, (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—(XXX)

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री रामेश्वर शर्मा—यह तरीका नहीं चलेगा..(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—(XXX)

अध्यक्ष महोदय—कृपया सीधी बात न करें, सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित.
(श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के बार-बार मना करने के बाद भी लगातार बोलने के कारण एवं श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य के साथ सीधे संवाद होने पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई)

(10.59 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई)

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

11.15 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए)

(सत्ता पक्ष की ओर से नारेबाजी किए जाने पर)

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- कृपया सभी बैठ जाएँ...(व्यवधान)..अब वे बैठ गए हैं...(व्यवधान)..कृपया बैठ जाएँ. श्री टेकाम अपना प्रश्न करो. (माननीय सदस्य श्री रामनिवास रावत के खड़े होने पर) कृपया बैठ जाएँ अब उनको प्रश्न करने दें. अब सब शांति है.

श्री रामनिवास रावत-- सत्ताधारी दल के विधायकों को भी तो हिदायत दे दें.

अध्यक्ष महोदय-- उनको बोल दिया है. वे सब बैठ गए हैं. व्यवस्था हो गई. आप प्रश्न पूछने देंगे कि नहीं. टेकाम जी, आप अपना प्रश्न पूछिए...(व्यवधान)..(सत्ता पक्ष के माननीय विधायक एक साथ खड़े होकर अपनी अपनी बात कहने लगे)..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- अब कृपया बैठ जाएँ...(व्यवधान)..दोनों पक्ष कृपया बैठ जाएँ...(व्यवधान)..आप लोग उनको प्रश्न पूछने देंगे कि नहीं...(व्यवधान)..तिवारी जी, बैठ जाइये...(व्यवधान)..

इंजी.प्रदीप लारिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सदन का समय खराब कर रहा है इनको बाहर होना चाहिए,(XX)...(व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी-- दौ कौड़ी का कहा है....(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- अब कृपा करके बैठ जाएँ...(व्यवधान)..यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है. आप लोग बार बार खड़े हो जाते हैं इसलिए व्यवस्था बिगड़ती है...(व्यवधान)..आप लोग प्रश्नकाल चलने देना चाहते हैं कि नहीं चलने देना चाहते हैं...(व्यवधान)..अब कृपा करके बैठ जाएँ...(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य-- हर महत्वपूर्ण प्रश्न पर तिवारी जी व्यवधान पैदा करते हैं...
(व्यवधान)..

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्र)-- जब सदन ठीक हो गया था तो फिर क्यों खड़े होना...(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत-- जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है उतनी ही जिम्मेदारी सत्तापक्ष की भी है.

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- सहमत हैं पर विपक्ष बार बार व्यवधान डालकर अनर्गल आरोप लगाएगा तो यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है.

श्री रामनिवास रावत-- हमारे सभी सदस्य शांत हैं. जो कुछ भी...

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- यह शांत हैं सदस्य. प्रश्नकाल को बाधित कर रहे हैं और आप शांत कह रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत-- यह किस नियम प्रक्रिया के तहत है कि तिवारी जी को बाहर करिए...(व्यवधान)..

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- यह किस नियम प्रक्रिया के तहत है कि प्रश्नकाल को बाधित करो...
(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य-- यह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं...(व्यवधान)..

सहकारिता मंत्री (श्री गोपाल भार्गव)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, 20-20 प्रश्नों की तैयारी करके आए हैं और आप लोग चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं. मैंने रात भर पढ़ा है और आप चर्चा नहीं होने देना चाहते.(XX)....(व्यवधान)..

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- माननीय अध्यक्ष महोदय, रात भर मंत्री पढ़ता है...(व्यवधान)..

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- यह भ्रष्टाचार को बंद कर दें...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप सब लोग कृपा करके बैठ जाएँ...(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी चर्चा अभी हुई है..

श्री गोपाल भार्गव-- मैंने रात भर पढ़ा है आँखों में दर्द हो रहा है आप लोग समझ नहीं रहे हों बात को...(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत-- जो भी चर्चा अभी हुई है उसको कार्यवाही से निकाल दें.

अध्यक्ष महोदय-- मेरा आप से अनुरोध है..

श्री रामनिवास रावत-- मेरा निवेदन है कि उन्होंने प्रजातंत्र के हत्यारे कहा...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- मैं उसको देख लूंगा...(व्यवधान)..उसके बाद में फिर निर्णय करूंगा.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र का...

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, आप इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते. मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं उसको देख लूंगा. देखने के बाद निर्णय कर लूंगा.

श्री रामनिवास रावत-- उन्होंने बोला है...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपा करके बैठ जाएँ और प्रश्नकाल चलने दें. मैंने आपकी बात सुन ली और मैंने आपको यह बता दिया कि मैं उसको पढ़ लूंगा और देख लूंगा. उसके बाद में व्यवस्था करूंगा. आप कृपा करके बैठ जाएँ.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन यह है कि जो भी असंसदीय...

अध्यक्ष महोदय-- अब हो गई बात. आप कृपया बैठ जाएँ. आप मुझे उसका निर्णय करने दें. आपने अपनी बात रख दी...(व्यवधान)..मैंने आपकी अपील सुन ली और मैं आपको आश्वस्त भी कर रहा हूँ कि मैं उसको पढ़ूंगा, देखूंगा...(व्यवधान)..कृपा करके बैठ जाएँ उनका आज कम से कम एक प्रश्न तो हो जाने दें.

श्री रामनिवास रावत-- उस प्रश्न में हमें कोई आपत्ति नहीं.

अध्यक्ष महोदय--बस तिवारी जी को ही है आपत्ति...(व्यवधान)..तिवारी जी बैठ जाइये...(व्यवधान)..एक प्रश्न तो होने दीजिए. बार बार खड़े हो रहे हैं यह क्या तरीका है आप लोगों का.

कृपया बैठ जाइये...(व्यवधान)..आप प्रश्न पूछने देंगे कि नहीं. आप उनको प्रश्न करने दें. आप कृपा करके बैठ जाएँ...(व्यवधान)..आपका व्यवहार भी कोई ठीक नहीं है. आप प्रश्नकाल में बार बार खड़े हो रहे हैं. मैं आप से बार बार अनुरोध कर रहा हूँ...(व्यवधान)..कृपा करके सभी बैठ जाएँ...(व्यवधान)..सुरेन्द्र सिंह जी आप कृपया बैठ जाइये. कृपया सब बैठ जाएँ. टेकाम जी, आप अपना प्रश्न करिए.

पात्र ग्रामों को योजना से जोड़ा जाना

1. (*क्र. 473) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत विकासखण्ड कुसमी, मझौली एवं देवसर में कितने राजस्व ग्राम हैं ? जनसंख्या सहित जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कितने ग्रामों को जोड़ दिया गया है एवं कितने ग्राम प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ने शेष हैं ? जानकारी उपलब्ध करायें ? (ग) प्रश्नांक (ख) के संदर्भ में जितने ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जोड़ने शेष हैं, उन्हें कब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा ? समय सीमा बतायें ? (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उनका मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है ? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अन्तर्गत कुसमी, मझौली एवं देवसर विकासखण्ड में क्रमशः 130, 130 एवं 218 राजस्व ग्राम हैं शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है । (ग) सीधी जिले के कुसमी एवं मझौली विकासखण्ड में क्रमशः 16 एवं 2 ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पात्र ग्राम जुड़ना शेष है किन्तु उक्त ग्राम क्रमशः रिजर्व फोरेस्ट क्षेत्र एवं निजी भूमि होने के कारण सड़क निर्माण नहीं कराया जा सकता है जबकि सिंगरौली जिले के देवसर विकासखण्ड के 24 पात्र ग्राम जुड़ना शेष है जिसमें से 12 ग्रामों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है एवं 10 मार्गों के डीपीआर तैयार कर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत शासन को भेजे गये हैं, स्वीकृति अपेक्षित है । दो ग्रामों के स्वीकृत कोरनेटवर्क में सम्मिलित नहीं होने से जोड़ा नहीं जा सका है । उक्तानुसार यथा संभव कार्यवाही की जा रही है । निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है । (घ) जी हाँ । पैकेज की पूर्णता तिथि से आगामी 5 वर्ष तक गारंटी अवधि में मार्ग का मरम्मत कार्य, मार्ग निर्माण करने वाले ठेकेदारों से कराया जाता है । गारंटी अवधि पश्चात आगामी 5 वर्षों के लिए नवीन एजेन्सी निर्धारित कर संधारण कार्य कराया जाता है ।

श्री कुंवर सिंह टेकाम-- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे मार्गों का निर्माण माननीय मंत्री जी द्वारा और सरकार के द्वारा कराया गया है उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा . लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र भी हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर अभी भी सड़कें नहीं हैं. प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण भी वहाँ पर नहीं हो पा रहा है. मैं मंत्री जी यह चाहूंगा कि वहाँ पर पांच-सात पुलिया हैं, यदि उनका निर्माण करा दें तो आवागमन अच्छे से हो सकता है .

श्री गोपाल भार्गव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि रिजर्व फारेस्ट में पीएमजीएसवाई की सड़कों का , पक्की सड़कों का निर्माण नहीं होता है मैं माननीय वनमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहाँ पर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कुछ पुलिया जो अपेक्षित हैं, वह बनवाने की कृपा करेंगे.

वनमंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार--- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग में जहाँ कोर जोन है, वहाँ पर कोई निर्माण होता नहीं है यदि आरईएस और ग्रामीण विकास विभाग वन विभाग को पैसा हस्तांतरित कर देगा तो हम उसमें निर्माण करवा सकते हैं.

श्री कुंवर सिंह टेकाम-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने और वनमंत्री जी ने इसका समाधान निकाला है उसके लिए धन्यवाद. मेरा दूसरा छोटा सा और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो ग्रामों में निजी भूमि पर सड़क बनाया जाना है, हमारे यहाँ ऐसे दो गांव हैं, जहाँ पर अभी भी सड़क नहीं बन पा रही है और कई बार ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है. मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी भूमि अधिग्रहण कर इन ग्रामों में सड़क का निर्माण कराएंगे क्या?

श्री गोपाल भार्गव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अंतर्गत जो सड़कों का निर्माण होता है इसमें भूमि अधिग्रहण का प्रावधान नहीं होता है इसमें एक ग्राम शेर है, जिसकी आबादी 271 है यह भी इसी कारण से शुरू नहीं हो पाया और दूसरा गांव

अमडेहा है जिसकी आबादी 1178 है यह छठवें फेज में स्वीकृत है परन्तु जमीन की उपलब्धता न होने के कारण यह काम नहीं हो पाया था . अध्यक्ष महोदय , मैं यथासंभव प्रयास करूंगा ग्रामसभा की बैठक लेकर कि वहाँ के किसानों को समझा के और जिनकी भूमि इसमें फंस रही है उनके लिए समझाने की कोशिश करूंगा और वहाँ पर मैं यह सड़क बनवाने का काम शीघ्र अति शीघ्र प्रारंभ कराऊँगा.

श्री कुंवर सिंह टेकाम-- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सारे प्रयत्न करके देख लिये हैं . कलेक्टर भी वहाँ गये थे लेकिन वहाँ पर किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं एक गांव का 30 लाख रुपये और दूसरे गांव का 45 लाख रुपये भू-अर्जन के लिए वहाँ से प्राक्कलन भेजा गया है यदि आप स्वीकृति दे देंगे तो यह कार्य हो जाएगा. यह दो गांवों का मामला है इसमें कितने लोगों को लाभ होगा इसकी व्यवस्था करवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी.

श्री गोपाल भार्गव – अध्यक्ष महोदय, इस विभाग में जो भी सड़कें बनती हैं उसमें भू-अर्जन के लिए राशि देने का प्रावधान नहीं है. भू-अर्जन करने का प्रावधान नहीं है किन्तु मैं यह प्रयास करूंगा कि अन्य किसी विभाग या लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखूंगा उसमें यदि वह विभाग भू-अर्जन के लिए राशि देता है तो मैं कोशिश करूंगा कि उससे यह काम मंजूर होकर निर्माण शुरू हो जाए.

गरीबों को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाना

2. (*क्र. 56) श्री मुकेश नायक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या के लिये सस्ते राशन पाने की पात्रता के संबंध में कुल कितने राशन कार्ड मार्च 2014 तक जारी किये गये ? (ख) इन कार्डों के आधार पर सस्ता राशन पाने वाली कुल जनसंख्या कितनी है ? (ग) वर्तमान में सस्ता राशन उपलब्ध कराने की सरकारी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह, प्रति व्यक्ति कितना अनाज किस कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) मध्यप्रदेश में मार्च 2014 तक अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 16,88,467 परिवारों को एवं प्राथमिकता परिवार के अंतर्गत सम्मिलित बी.पी.एल. श्रेणी

के अंतर्गत 59,36,184 परिवारों को सस्ता राशन पाने के लिए पात्रता पर्ची जारी की गई थी। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित परिवारों की कुल जनसंख्या मार्च 2014 की स्थिति में 3,27,27,509 थी। (ग) वर्तमान में लक्षित सार्वजनिक प्रणाली अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रतिमाह 35 कि.ग्रा. प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रतिमाह 5 कि.ग्रा. प्रति सदस्य के मान से 1 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री मुकेश नायक-- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न(क) के उत्तर में यह कहा है कि मध्यप्रदेश में 3,27,27,509 कार्डधारी हैं. मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि बीपीएल कार्ड में जो नये नाम जुड़े हैं और जो पुराने नाम हैं. जो डाटा या संख्या माननीय मंत्री जी ने बतायी है. हम अभी देहातों में दौरे पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि राशन नहीं मिला, उसका कारण जब हम उनसे पूछते हैं तो वह कहते हैं कि यह पूरा डाटा कम्प्यूटराइज्ड कर दिया गया है और इस कारण से कम्प्यूटर में यह नाम दर्ज नहीं हो पाया है. जब हम उनसे पूछते हैं कि किन कारणों से यह दर्ज नहीं हो पाया है तो गांव के लोग बताते हैं कि गांव में रोजगार सहायक ने यह डाटा फीड नहीं किया. जब रोजगार सहायक से हम पूछते हैं कि यह डाटा फीड क्यों नहीं किया तो वह कहता है कि सर्वर डाउन हो गया. मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि यह आपका कौन सा सर्वर है जो डाउन हो जाता है और जिसके कारण तीन-तीन महीने से किसानों की पर्चियां फीड नहीं हो पायीं और राशन का वितरण नहीं हो पाया. माननीय मंत्री जी बतायें कि एक साल से जो डाटा फीड नहीं हो पाया तो कब तक यह काम पूरा कर लेंगे?

कुँवर विजय शाह-- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने किस जिले की जानकारी चाही है, वह स्पष्ट नहीं है.

श्री कमलेश्वर पटेल-- पूरे प्रदेश का मामला है.

कुँवर विजय शाह-- पूरे प्रदेश की जहां तक मुझे जानकारी है, मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध है. पहले केवल 50 प्रतिशत लोगों को ही इसका लाभ मिलता था लेकिन अभी पौने दो करोड़ लोग अतिरिक्त जुड़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिये थे कि जो भूमिहीन हैं, जो गरीब हैं, दूसरे घरों में काम करने वाले हैं, हम्माल हैं, कुली हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के वे लोग हैं, इनको मिलाकर के जितने बीपीएल और अत्यन्त गरीब के कार्ड थे उनसे ज्यादा लोग अभी लाभ

ले रहे हैं। अगर किसी जिले विशेष की शिकायत है, जैसे आपका कहना है कि वहां पर सर्वर डाउन हो गया तो हम चेक करके आपको बता सकते हैं।

श्री मुकेश नायक-- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पन्ना जिले के Statistical India के सर्वे में भारत का सबसे गरीब जिला माना गया है। मैं पन्ना जिले की बात कर रहा हूँ और कमोवेश जैसे सम्मानित सदस्य बोल रहे हैं चाहे वे कांग्रेस पक्ष के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के हों, यह प्रदेश की एक कॉमन समस्या है जिससे सब हितग्राही जूझ रहे हैं। जो नये कार्डधारक हैं, जो पर्ची आपने बना दी है, पौने दो करोड़ जिन लोगों की आपने बात की, ये डाटा कम्प्यूटराइज्ड नहीं हो पाया है, उसके कारण जो जिला खाद्य अधिकारी है, इनके राशन का आहरण नहीं कर रहा है जिसके कारण इनको राशन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, मुझे यह बताने की कृपा करें कि राशन बांटने की कोई तारीख जिलों में आपने तय की है या नहीं की है? आप 29 तारीख को राशन बांटते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि एक महीने का राशन दुकानदार पूरा हड़प कर जाते हैं। क्या आपने यह तय किया है कि किस तारीख को पूरे मध्यप्रदेश में राशन का वितरण होगा? जैसे विधायकों को पहली तारीख को उनकी तनख्वाह उनके अकाउन्ट में ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे ही क्या आपने तय किया है कि गरीब आदमी को राशन बांटने की कोई तारीख तय होगी?

कुँवर विजय शाह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जितनी भी राशन की दुकानें हैं वह कोई सप्ताह में तीन दिन खुलती हैं, वहां पर दिन निश्चित रखे हैं और हर दुकान पर लिखे हुए हैं जैसे सोमवार, मंगलवार या बुधवार या जहां पर पूरे समय सेल्समेन हैं वहां पर सभी दिन दुकान खुलती है और जहां पर सेल्समेन कम हैं वहां पर दिन निश्चित हैं उन दिनों पर पूरे महीने दुकान खुलती है।

श्री मुकेश नायक- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को विनम्रतापूर्वक यह जानकारी देना चाहता हूँ कि जो आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूरा सिस्टम बना रखा है,

यह पूरा चकनाचूर हो गया है. आप इस पर पुनर्विचार करें. क्या आप अधिकारियों को निर्देश देंगे कि समय पर दुकान खोली जाएं, समय पर राशन बांटा जाए. कोई तारीख तय हो, आप यहां से तय कर दें कि आप हर महीने एक से लेकर तीन तारीख तक राशन बांटेंगे. सोमवार, मंगलवार, बुधवार का इसमें क्या प्रश्न है. आप सदन को बतायें कि आप ऐसा करेंगे क्या?

कुँवर विजय शाह – माननीय अध्यक्ष जी, हमने पूरे निर्देश दे रखे हैं. जहाँ पर सेल्समेन के पास एक दुकान है, वह रोज खोलता है. जहाँ के सेल्समेन के पास दो दुकानें हैं या तीन दुकानें हैं, उनके दिन निर्धारित कर दिए गए हैं, पूरे महीने निश्चित किए हुए दिनों में दुकानें खुलती हैं. आदमी कभी भी आ जाए और कभी भी राशन ले जाए.

श्री मुकेश नायक -- माननीय अध्यक्ष महोदय, हर दस दिन में सेल्समेन बदल जाता है.

कुँवर विजय शाह -- दूसरा, हमने यह निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति उस महीने का राशन नहीं ले पाता है तो उसको अगले महीने डबल राशन लेने की पात्रता मिलेगी. वह दो महीने का राशन एक साथ ले सकता है. ये आदेश जारी हो गए हैं.

श्रीमती ऊषा चौधरी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महीने का तो पहले दिलवाइये. 5-6 महीने से नहीं मिल रहा है.

श्री जीतु पटवारी -- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये पार्टी का नीतिगत प्रस्ताव है और सम्माननीय सभी सदस्य इसमें सहमत हैं. सब इस मुद्दे से परिचित हैं और खासकर जनप्रतिनिधि.

श्रीमती ऊषा चौधरी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पूर्व सत्र में वायदा किया था कि एक महीने के अंदर हर पंचायत में नया सेल्समेन नियुक्त किया जाएगा, वह आज तक नहीं हुआ है, दो-दो, तीन-तीन महीने का राशन नहीं मिला है.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्नकाल समाप्त

(प्रश्नकाल समाप्त)

स्थगनप्रदेश के अनेक जिलों में स्वाइन फ्लू के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति

अध्यक्ष महोदय:- प्रदेश के अनेक जिलों में स्वाइन फ्लू का प्रकोप होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:-

पहली सूचना
दूसरी सूचना
तीसरी सूचना

डॉ. गोविन्द सिंह
श्री आरिफ अकील
श्री रामनिवास रावत

सदस्य की है।

चूंकि डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की सूचना पहले प्राप्त हुई अतः मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं :-

ग्वालियर, जबलपुर, खण्डवा, देवास, धार, बड़वानी, हरदा, शाजापुर, इंदौर, श्योपुर जिले एवं राजधानी भोपाल सहित समूचा प्रदेश इन दिनों संक्रामक एवं जानलेवा बीमारी स्वाइन फ्लू की चपेट में है जिससे लगातार होने वाली मौतों का सिलसिला जारी है, किन्तु प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा तमाशा देख रहा है। दिनांक 9.2.2015 को एम.वाय.एच. हॉस्पिटल इंदौर में मध्य रात्रि से दिनांक 10.2.2015 को सांयकाल तक मात्र 17 घंटे में स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से हो चुकी है जिनमें सबसे ज्यादा 19 मरीजों की मौत इंदौर में हुई है। ग्वालियर के जयारोग्य हॉस्पिटल सहित अन्य शासकीय अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए न तो टेमीफ्लू नामक दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है न ही सेम्पल कलेक्शन के लिए किट उपलब्ध है जिन वार्डों को स्वाइन फ्लू पेशेंट के लिए बनाया गया है वहां पर

पर्याप्त संख्या में वेंटीलेटर, मास्क एवं आक्सीजन सिलेन्डर नहीं है। इसके साथ ही चिकित्सकों की लापरवाही एवं उदासीनता के चलते एवं प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में भी समय पर स्वाइन फ्लू का उचित उपचार नहीं मिलने से मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसे प्राथमिक स्तर पर ही रोकने की बजाय केवल आंकड़ों के खेल में ही उलझा हुआ है। विभाग द्वारा इस बीमारी की रोकथाम, पहचान हेतु एवं जागरूकता हेतु समुचित प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। स्वाइन फ्लू से लगातार हो रही मौतों को लेकर आम जनता में तीव्र रोष व आक्रोश व्याप्त है

अतः आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराई जाय।

इसके संबंध में शासन का क्या कहना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य चाहें, ग्राह्यता पर चर्चा तो ग्राह्यता पर तैयार हैं।

श्री रामनिवास रावत -- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकार ही कर लिया जाए.

अध्यक्ष महोदय -- क्या स्वीकार है ?

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- स्वीकार है.

अध्यक्ष महोदय -- चूँकि शासन इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य किए जाने के पक्ष में है, अतः मैं इसे ग्राह्य कर चर्चा प्रारंभ करता हूँ, डॉ. गोविंद सिंह.

श्री रामनिवास रावत -- माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण वगैरह विषय समाप्त होने के बाद ले लेते.

अध्यक्ष महोदय -- उसके बाद में ले लेंगे.

श्री रामनिवास रावत -- ध्यानाकर्षण बाद में जाएंगे.

अध्यक्ष महोदय -- ध्यानाकर्षण भी ले लेंगे, पहले भी हो चुका है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- आप विषय उठाने के पहले सोचा करो, हर बार आप ऐसी स्थिति कर देते हो.

श्री रामनिवास रावत -- विषय इसी समय उठाया जाता है. ग्राह्य होने के बाद लंच ऑवर के बाद जाता है.

अध्यक्ष महोदय -- माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि ध्यानाकर्षण भी लेंगे. अभी अपने पास समय है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- ग्राह्य होने के बाद ध्यानाकर्षण लेने की परम्परा नहीं है.

श्री रामनिवास रावत -- ग्राह्य होने के बाद तो स्थगित होती है.

अध्यक्ष महोदय -- चर्चा हो रही है और समाप्त हो जाता है अपने आप. आप नियम पढ़ लीजिए. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो जाती है, शासन का उत्तर आ जाता है, इसके बाद स्थगन प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है. बाद में ध्यानाकर्षण लिए गए हैं, इसके पूर्व उदाहरण हैं.

डॉ.गोविन्द सिंह-माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले सूचना तो मिलनी चाहिए.

अध्यक्ष महोदय- स्थगन प्रस्ताव की सूचना तो आपकी ही रहती है.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा- इनको सूझ नहीं पड़ रही है कि अब क्या करें.

श्री राम निवास रावत- आल राऊण्डर हैं, तैयारी की जरूरत नहीं है.उन्हें पूरे प्रदेश की जानकारी पता है.(व्यवधान)

श्री के.पी.सिंह- अध्यक्ष महोदय, अक्सर सदन में यह हो रहा है कि जब तैयारी करके आते हैं तो लेते नहीं हैं और जब सोचते हैं कि शायद बाद में लिया जाएगा तो कहते हैं चर्चा चालू करो. नरोत्तम मिश्राजी ने एक नया तरीका निकाला है, जब उन्हें तय लग जाता है कि तैयारी नहीं है तो कहेंगे कि अभी चर्चा चालू करो. यह मिश्राजी ने नया तरीका निकाला है.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा- अध्यक्ष जी, आप साक्षी हैं, मुख्य सचेतक कांग्रेस विधायक दल ने कल आपसे अनुरोध नहीं किया था? (व्यवधान) आप पूरी बात सुनिये, मुख्य सचेतक कांग्रेस विधायक दल ने शून्यकाल होते ही तत्काल इस विषय को उठाया था. विषय उठायेंगे तो चर्चा करेंगे नहीं ?

श्री राम निवास रावत- तैयार हैं , भैया तैयार हैं, चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा- आप के.पी.सिंह जी से यह बात कहो ,आपके दल के लोग आपकी बात सुनते नहीं है. अभी तिवाजी जी चले गये, वो खड़े हो जाते तो आप क्या कर लेते?

श्री राम निवास रावत- तिवारी जी, तैयारी करने गये हैं.

श्री के.पी.सिंह- अध्यक्ष जी, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा जब स्थगन पर चर्चा होती थी तो एक समय निश्चित कर देते थे कि इतने बजे से स्थगन पर चर्चा करेंगे

अध्यक्ष महोदय- दोनों ही बातें हैं.(व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा- अध्यक्ष महोदय..

श्री के.पी.सिंह- मंत्री जी एक मिनट, पूरी बात सुनने में आपको क्या दिक्कत है? चर्चा तो कर ही रहे हैं, डॉक्टर साहब पूरी तैयारी से आए हैं. आप चिन्ता मत करो, आपके लिए तो डॉक्टर साहब हमेशा तैयार रहते हैं. उनकी पूरी तैयारी है, राम निवास रावत जी की पूरी तैयारी है. अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि किसी भी विषय पर जब स्थगन दिया जाता है तो कम से कम पहले से तय कर दें कि चर्चा तत्काल चालू करेंगे या कब से लेंगे. उससे क्या होता है कि कई सदस्यों को पता लग जाता है कि चर्चा बाद में होगी तो वे अनुपस्थित हो जाते हैं, मौके पर होते ही नहीं हैं. एक बार इसी सदन में हो चुका है. व्यापम वाले मामले में इसी तरह से चर्चा चालू हुई, उन्होंने कहा तत्काल चर्चा चालू करो. मेरा अनुरोध सुन लें, मुझे चर्चा होने में कोई एतराज नहीं है.

श्री गोपाल भार्गव-- ऐसा कभी नहीं हुआ कि सदस्यों के लिए पूर्व में अवगत कराया गया हो.

श्री के.पी.सिंह- हमेशा स्थगन के मामले में समय तय कर दिया जाता है कि लंच के बाद स्थगन पर चर्चा करेंगे. ऐसा हुआ है.

अध्यक्ष महोदय- ठीक है, आप बैठ जाएं. जब भी माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव देते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि उसकी तैयारी स्थगन देते समय ही करें. यह बात उचित नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव पहले दे दें और तैयारी के लिए बाद में समय चाहें. सावधानी में ही सुरक्षा होती है. इसलिए हमेशा सावधान रहना ठीक है.

श्री कैलाश विजयनवर्गीय- वैसे डॉ.गोविन्द सिंह को जब से मैं जानता हूं उन्होंने कभी होमवर्क नहीं किया. हमेशा पढ़ाई में भी वो जिस प्रकार पास होते थे वह बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनको होमवर्क की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती.

डॉ.गोविन्द सिंह - आप भी हमारे जैसे ही हैं.

श्री गोपाल भार्गव-- अच्छा यदि पढ़ा हो तो बतायें कि स्वाइन फ्लू का हिन्दी में नाम क्या है?

श्री कमलेश्वर पटेल- अध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर विषय है, इस पर इस तरह से हास परिहास नहीं होना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय- हां, कृपा करके डॉक्टर गोविन्द सिंह को अपनी बात कहने दें.

श्री गोपाल भार्गव-- उत्तर अभी बता देंगे तो उत्तर असली नहीं तो नकली.

श्री कमलेश्वर पटेल-- अध्यक्ष महोदय, आये दिन लोग मर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है.

अध्यक्ष महोदय-- आपकी बात ठीक है, कृपया इसको गंभीरता से लें.

डॉ.गोविन्द सिंह-- अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है.

राज्यमंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (श्री शरद जैन)- डॉक्टर साहब कौन से समय की जानकारी दे रहे हैं, दस साल पुरानी जानकारी दे रहे हैं क्या?

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाएं.

डॉ. गोविन्द सिंह - आप कितने योग्य राज्यमंत्री हैं, अभी बताएंगे. पूरे प्रदेश में महामारी और संक्रमित रोगों के लिए मध्यप्रदेश शासन ने लोक स्वास्थ्य गारंटी योजना प्रारंभ की है और उसके तहत अनेक महामारियों के साथ-साथ स्वाइन फ्लू भी इसमें शामिल था. प्रदेश सरकार ने जब अपनी लोक स्वास्थ्य गारंटी योजना प्रारंभ की, उस समय से भी इन बीमारियों के लिए सभी प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य केन्द्रों तक इन दवाइयों की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए थी. परन्तु सरकार अपनी कथनी-करनी से दूर केवल भाषणबाजी और असत्य वाचन करने की आदी हो चुकी है. प्रदेश में पिछले महीनों में डेंगू की महामारी फैली. सरकार ने उससे सबक नहीं लिया. धीरे-धीरे प्रदेश में डेंगू की महामारी के बाद स्वाइन फ्लू का प्रकोप चालू हुआ. आज पूरे मध्यप्रदेश में ऐसा कोई जिला और गांव नहीं बचा, जहां पर स्वाइन फ्लू के एक-दो मरीज न मिल रहे हों. कई लोगों में जांच में यह पाया गया. अधिकांश गांवों में लोगों को जानकारी नहीं रहती कि स्वाइन फ्लू क्या है? इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि दीपावली पर मैं अपने गांव गया था. गांव में श्रीमती सुनिता पत्नी श्री गंगा सिंह आयु 45 वर्ष की स्वाइन फ्लू में मृत्यु हुई. मैंने पूछा था तो बताया कि दो दिन खांसी-बुखार आया था, सिरदर्द हुआ, गले में तकलीफ हुई, खराश हुई और लोग समझ नहीं पाए. गांव में ही इंजेक्शन लेते रहे. बीमारी की गंभीरता की न तो गांवों में जागरूकता है. न लोगों यह पता रहता है कि यह इतनी गंभीर बीमारी है, इतना वायरल इनफेक्शन गंभीर है. उस महिला की मृत्यु हो गई. इसके बाद ही आसपास के करीब 8-10 गांवों में क्रम से मौतें होती गई. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब स्वाइन फ्लू लगातार पूरे प्रदेश में फैल गया, जिला चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजों में, बड़े महानगरों में जब स्वाइन फ्लू से तमाम मरीजों की मौत होने लगी, तब तक सरकार की नींद नहीं खुली.

माननीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री शरद जैन साहब, 8 फरवरी 15 को जबलपुर में बताते हैं कि हमारे प्रदेश में स्वाइन फ्लू का एक भी मरीज जांच में नहीं पाया गया. जबकि उसके पहले स्वाइन फ्लू से ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में ही तीन लोगों की मौत हो चुकी थी.

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (श्री शरद जैन)- माननीय डॉक्टर साहब, मैंने जो जानकारी दी थी, जिन जिलों में मैं होकर आया हूं. आज भी मैं कह रहा हूं कि मंडला में एक भी नहीं है. आज भी मैं कह रहा हूं कि डिंडौरी में एक भी नहीं है. जहां की समीक्षा बैठक हुई, वहां की जानकारी दी है.

श्री मुकेश नायक - क्या आप विधान सभा में स्वाइन फ्लू का समर्थन कर रहे हैं ? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, कितने गंभीर विषय पर बातचीत हो रही है.

श्री शरद जैन - अध्यक्ष महोदय, मैं भी तो उतनी ही गंभीरता से बात कर रहा हूं.

श्री के.पी. सिंह - आप जिले के मंत्री हैं कि पूरे प्रदेश के मंत्री हैं?

श्री शरद जैन - मैं पूरे प्रदेश का मंत्री हूं.

श्री के.पी. सिंह - तो फिर आप पूरे प्रदेश की बात करें.

श्री शरद जैन - लेकिन मेरे नाम का उल्लेख किया गया है. जिस स्थान का उल्लेख किया गया है, उस स्थान की जानकारी दे रहा हूं.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि सदन में यह प्रस्ताव पारित कर दो कि यह स्वास्थ्य राज्यमंत्री हर जिले में पहुंच जाएं ताकि स्वाइन फ्लू इनके डर के मारे अपने आप भग जाएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जहां-जहां इनके कदम पड़ते हैं, वहां यह अपने आप गायब हो जाता है. जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं तो क्या जरूरत है दवाइयां मंगाने की, क्या जरूरत है लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करने की? अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 4500 डॉक्टर्स नहीं हैं. भिंड जिले में ही 60 प्रतिशत ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां चिकित्सक नहीं हैं. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कई

जिलों में एक भी महिला चिकित्सक नहीं है। जब चिकित्सक ही नहीं होंगे तो कैसे जांच होगी, कैसे पता चलेगा कि यह स्वाइन फ्लू है?

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रमुख सचिव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी दौरा करने गये। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्र जब से बने हैं, पूरी स्वास्थ्य की व्यवस्था को उन्होंने चौपट कर दिया है. (XX) . पूरा स्वास्थ्य विभाग चरमरा चुका है। आयुर्वेदिक अस्पतालों में 80 प्रतिशत में डॉक्टर नहीं हैं। जब पूरा स्टॉफ ही नहीं होगा, कहीं व्यवस्था नहीं होगी तो आखिर जांच कौन करेगा? पता कैसे चलेगा कि कौन-से व्यक्ति को कौन-सी बीमारी है? इसके साथ-साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अभी तक मध्यप्रदेश में कल तक जो रिपोर्ट है उसमें 89 मरीज हैं जिनकी मौत सरकारी आंकड़ों के अनुसार हो चुकी है। प्रमुख सचिव महोदय गये, अभी तक हम इनकी तारीफ करते थे क्योंकि यह तत्काल एक्शन लेते थे लेकिन पता नहीं किस दवाब में आकर इन्होंने इंदौर में कह दिया कि कोई मरीज ही नहीं है। निजी चिकित्सालयों को कह दिया कि आप स्वाइन फ्लू का इलाज नहीं करेंगे। अगर कोई जान बचा रहा है-- वैसे लगातार स्वाइन फ्लू जिंदगियां लील रहा है-- तो इस तरह का व्यवहार प्रमुख सचिव जी का नहीं होना चाहिए। उनको बात की गंभीरता को देखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब जेपी अस्पताल में गये जब उनको पता चला तो उन्होंने घोषणा की कि हम निजी चिकित्सालयों को भी स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि उपलब्ध करायेंगे। लेकिन आज तक किसी निजी चिकित्सालय में कोई भी राशि मध्यप्रदेश की सरकार ने - जो अस्पताल चिन्हित किये थे - हो सकता है कि भोपाल के किसी अस्पताल में पहुंच गई होगी लेकिन ग्वालियर संभाग में तो मैंने कई निजी चिकित्सकों से जानकारी ली है वहां पर कोई भी किसी भी तरह की सुविधा मध्यप्रदेश शासन द्वारा नहीं दी गई है। जब बीमारी पूरी तरह से लाइलाज हो गई है तब जाकर सरकार की नींद खुलती है, तब जाकर केन्द्रीय मंत्री से निवेदन करते हैं उसके बाद में केन्द्र सरकार से कुछ दवाएं आती हैं। टेमूफ्लू टेबलेट राजस्थान और दिल्ली से मंगाना पड़ा है।

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित

हमारा प्रदेश आबादी के मामले में विकसित राष्ट्र है कर्मण पुरस्कार और ना जाने कौन कौन से फर्जी पुरस्कार लेने के आप आदी हो गये हैं.

श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर -- कृषि कर्मण पुरस्कार किसानों का सम्मान है. किसान मेहनत कर रहे हैं...(व्यवधान).. आप यहां पर यह कहकर मध्यप्रदेश के किसानों का अपमान कर रहे हैं.

डॉ. गोविन्द सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय जब माननीय मुख्यमंत्री जी जेपी अस्पताल में गये तब जाकर बेड शीट बदली गई. वहां पर उनको यह दिखाने के लिए की बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है परफ्यूम छिड़का गया. आप इस तरह की व्यवस्था देखकर और अखबार में नाम छपवाकर वाह वाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं, इसको कण्ट्रोल करें, मरीजों के लिए अस्पतालों में केवल एक लैब है वह भी जबलपुर में है. माननीय उच्चन्यायालय ग्वालियर ने भी निर्देश दिये हैं कि आप प्रदेश में अन्य लैब खोलें. आप बड़े बड़े महानगरों में खोल सकते हैं. आपके पास में स्वाइन फ्लू की टेबलेट नहीं है, आपके पास में मास्क नहीं है पूरी तरह से इसकी कालाबाजारी हो रही है. ग्वालियर में एक डॉ. रवि रमन है हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं एचओडी हैं. परसों में उनसे मिला था उन्होंने बताया कि 5 रुपये की टेमूफ्लू टेबलेट है उसे राज मेडीकल स्टोर कभी 200 रुपये में दे रहा है जब डॉक्टर पर्चे में लिख रहे हैं तो देता नहीं है. आपका जो मास्क ट्रिपल फिल्टर एल 95 है जिसकी कीमत 250 है बाजार में 500 से 700 रुपये में बिक रहा है, एल 95 नार्मल मास्क है 120 रुपये के स्थान पर 220 रुपये से लेकर 250 रुपये तक बिक रहा है, और नार्मल मास्क जो कि 5 रुपये में बिकना चाहिए वह 40 रुपये में बिक रहा है. आपके एम्स तक में व्यवस्था नहीं है. एम्स में भी ना तो जांच हो रही है ना ही दवाएं हैं. वहां से तमाम मरीज लौट रहे हैं. यहां पर भोपाल में सभी समाचार पत्रों में खबर छपी है. आपके यहां पर बड़े अस्पतालों को छोड़ दें तो जिला चिकित्सालयों में कहीं पर भी वेन्टीलेटर नहीं है. अगर वेन्टीलेटर नहीं है तो आप वहां पर आक्सीजन सीलेण्डरों की भरपाई कर सकते हैं. दवाएं भेज सकते हैं. आपने कहा था कि केन्द्र से पीपीई किट, हो सकता है भोपाल में हो, लेकिन कहीं पर भी बाहर बड़े अस्पतालों में नहीं पहुंच

पाई है. गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि उनके लिए फ्री करेंगे लेकिन जिन निजी चिकित्सालयों को चिन्हित किया है उन अस्पतालों में भी अभी तक आपकी ना तो टेम्प्लू टेबलेट मिली है, ना ही जांच के लिए किट मिली है. ग्वालियर में अभी दो दिन पहले तक मेडीकल किट की बहुत कमी थी. इसके अलावा संपूर्ण प्रदेश में लगातार मौतें हो रही हैं. इसके अलावा संपूर्ण प्रदेश में लगातार मौतें होना जारी है . मध्यप्रदेश के साथ साथ आसपास के राज्यों में वहां की सरकारों ने इस रोग की रोकथाम के लिये तत्काल कदम उठाये इसलिये वहां पर स्थिति नियंत्रण में है. हमारा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इस महामारी को रोकने के लिये आप पूरे प्रदेश में अभियान चलायें, इसके लिये राशि की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी व्यवस्था करें, वैसे प्रदेश सरकार का दीवाला निकल चुका है. वेतन बांटने के लिये 15 हजार सौ करोड़ रुपये ले रहे हैं. अगर आपको विधायकों की स्वैच्छा निधि से पैसा चाहिये तो लोगों की जान बचाने के लिये, गांव के गरीब कमजोर वर्ग के लोगों की जान बचाने के लिये यह पैसा कई लोग दे सकते हैं, इसके लिये आप निजी चिकित्सालयों में, निजी चिकित्सकों से जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे भी आप इस बीमारी की रोकथाम के लिये सहयोग ले सकते हैं ताकि प्रदेश में फैली महामारी पर नियंत्रण किया जा सके. अध्यक्ष महोदय, स्वाईन फ्लू का ग्वालियर और चंबल संभाग में ज्यादा प्रकोप है. भिंड में 7 मौतें, श्योपुर में 4, शिवपुरी में 5 और स्वास्थ्य मंत्री का जिला दतिया जहां पर आप मेडिकल कालेज ले गये हैं, छोटे से जिले, वहां पर भी स्टाफ नहीं है, आधे से ज्यादा डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, स्पेशलिस्ट के 60 प्रतिशत रिक्त हैं. आप अपना जिला जब स्वास्थ्य सेवाओं में नहीं सुधार सकते तो पूरे प्रदेश की आपसे क्या उम्मीद करें. स्वास्थ्य मंत्री जी आप इस पद के योग्य नहीं हो आपको तत्काल इस पद से हट जाना चाहिये और किसी योग्य व्यक्ति को यह मंत्रालय सौंप देना चाहिये, आपको एक क्षण भी इस पद पर बैठने का अधिकार नहीं है. अध्यक्ष महोदय, अंतिम बात और कहना चाहता हूं. (हाथ में पेपर की कटिंग लहराते हुये) यह फोटो मंत्री जी छपवा रहे हैं. विज्ञापन में ही करीब 10 करोड़

रूपये खर्चा कर चुके हैं , यही 10 करोड़ दवायें खरीदकर जनता तक पहुंचाते तो यह महामारी नहीं फेलती. (XX)

सभापति महोदय-- इसको कार्यवाही से निकाल दें. आरिफ अकील अपनी बात कहें.

[*] निर्देशानुसार विलोपित.

श्री आरिफ अकील (भोपाल उत्तर) -- अध्यक्ष महोदय, शासन का इस पर जबाव नहीं आयेगा क्या.

अध्यक्ष महोदय-- आखिरी में जबाव आयेगा.

श्री आरिफ अकील -- ठीक है. अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू के मामले में मेरा सीधा सीधा कहना है कि बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनके मंत्री और अधिकारियों के बीच में आपस में समन्वय नहीं है. वैसा ही विभाग स्वास्थ्य है. यहां के प्रमुख सचिव, सचिव मंत्री जी की सुनते नहीं है और मंत्री जी जो कहते हैं उसके अलग डायरेक्शन में वे जाते हैं. यह किसी और के कहने से काम करते हैं, आपके कहने से काम नहीं कर पाते हैं. यह बीमारी इतनी बढ़ गई है कि आप प्रेस कान्फ्रेंस छोड़कर के भागते हो, आप बहुत एक्सपर्ट आदमी हो, आपको संकटमोचक कहा जाता है , हर जगह आप प्रेस कान्फ्रेंस लेने पहुंच जाते हो लेकिन स्वाइन फ्लू के मामले में प्रेस वाले आपसे सवाल पूछते हैं तो आप भड़क जाते हैं यही हाल आपके प्रमुख सचिव जी का है कि वे प्रेस कान्फ्रेंस छोड़कर के चले जाते हैं, कहते हैं कि हमें प्रेस कान्फ्रेंस नहीं करना तो जब मंत्री और विभाग का प्रमुख सचिव इसके लिये प्रेस कान्फ्रेंस करेंगे नहीं, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं देंगे , समझायेंगे नहीं कैसे व्यवस्था चलेगी. मेरी इस बारे में मंत्री जी से पूर्व में भी चर्चा हुई है कि स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश में खराब हो रही है आप इसको देखें. आप बतायें कि इतने दिनों से यह महामारी फेल रही है आपने कहा कहा पर नई लेब बनाई, विज्ञापन पर तो आप करोड़ों रूपया खर्चा कर रहे हैं. क्या भोपाल में इसकी जांच हेतु कोई लेब बनाई, क्या इंदौर में लेब बनाई, क्या ग्वालियर में लेब बनाई. मेरा मानना यह

है कि जब यह बीमारी बढ़ती चली जा रही है तो इस बीमारी को रोकने के लिये आपको हर जिले में इसकी जांच हेतु लेब का गठन करना चाहिये ताकि लोगों को बीमारी का पता हो सके और समय पर इलाज हो सके. मास्क लगाने के लिये काम्पटीशन होता है. जब मुख्यमंत्री जी अस्पताल में गये (भाषण के दौरान खांसते हुये) मैं खांस रहा हूं इसलिये आपको शक हो रहा है कि कहीं मुझे तो स्वाईन फ्लू नहीं है. तो भैया जांच करा लो.

श्री कमलेश्वर पटेल -- अकील साहब जो अमानक स्तर की दवायें खा रहे हैं वह वैसे ही ठीक नहीं होंगे. प्रदेश में अमानक स्तर की दवायें बट रही हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, भगवान आरिफ अकील को बहुत लंबी उम्र दे.

श्री आरिफ अकील -- बीमारी तो किसी को भी हो सकती है. आपके मंत्री हंस रहे हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- आपको बीमारी न हो यह दुवा तो मैं कर सकता हूं.

श्री आरिफ अकील -- बस यही हो सकती है कि हम लोगों को ऐसे ही तड़पा तड़पा कर शायद बीमार रखना चाहते हो आप. अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, कई मंत्री ऐसे हैं, जो विभाग के सचिवों से काम नहीं करवा पाते हैं, नहीं कह पाते हैं. क्योंकि उनकी लगाम, नकेल उनके पास नहीं है, वह मात्र मुख्यमंत्री जी के हाथ में है. या तो मुख्यमंत्री जी कह दें कि सारे विभाग के मुख्यमंत्री वही हैं. वही सब व्यवस्थाएं देखेंगे. नहीं तो जिनको मंत्री बनाया है, जिनको विभाग दिया है, उनको यह जिम्मेदारी दें, उनके अधिकारियों को कहें कि आप अपने मंत्रियों की सुनोगे, उनकी व्यवस्था करोगे. अपनी बात अलग नहीं चलाओगे. मंत्री बनाया है इनको, लोगों ने चुना है इनको, ये जो आपको आदेश दे रहे हैं, उसका पालन करो. वे सुनने को ही तैयार नहीं हैं. आप कहते हो कि इसके इलाज की व्यवस्था कर दो, वह कहते हैं कि नियम में ही नहीं है. आप कहते हो कि यहां उस कम्पनी की दवा भेज दो, वह कहते हैं कि यह हम नहीं ले सकते हैं. तो ऐसा समन्वय बनगा कैसे. जब आप लोगों का आपस में समन्वय नहीं बनेगा, तो निश्चित ही कोई भी

बीमारी मध्यप्रदेश में फैलती रहेगी. तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से केबिनेट की बैठक में आप लोग कहो कि जो हमारे अधिकारी, पीएस, सीएस हैं, उनको यह आदेशित करें कि हम लोग जो व्यवस्था करें, जो बात कहें, उसको वे पूरी करें. आपने दवाओं के लिये क्या व्यवस्था की. करोड़ों रुपये का आप विज्ञापन तो दे रहे हैं, भास्कर में, दूसरे सब पेपर्स में आपका विज्ञापन छप रहा है, यह भी छप रहा है कि आप प्रेस कांफ्रेंस में, पहली मर्तबा सुना कि आप पलायन कर गये. मंत्री जी भाग गये प्रेस कांफ्रेंस छोड़ करके. क्यों भैया? ऐसी कौन सी आपको चिड़ हो गयी थी. या यह कह दो कि आपकी विभाग में नहीं चल रही है. तो उसकी व्यवस्था आप खुद करो. यह तो आपका अपना रोग है. जो आपके बड़े डॉक्टर साहब ने छोटे डॉक्टर को दिया. इस रोग का इलाज तो बड़े डॉक्टर से स्वयं कराओ. हम लोगों को आप क्यों इनवॉल्व करते हो. मध्यप्रदेश की जनता इससे क्यों सफर करे. उसकी परेशानी का ध्यान रखो. ...

श्री उमाशंकर गुप्ता -- अकील जी, आपको गलत जानकारी मिली होगी. नरोत्तम जी को देखकर तो बाकी लोग भागते हैं. कुछ गलत जानकारी आपको मिली होगी.

श्री आरिफ अकील -- आज कल तो आप अपनी व्यवस्था बनाने के लिये नये नये हथकण्डे अपना रहे हो कि बच जाओ, बच जाओ. लेकिन जब सफाया होगा, तो आपका भी सफाया होना है. तो आप भी नहीं बचने वाले हो. बेफिक्र रहो.

श्री बाबूलाल गौर -- आप बदुआ तो मत दो.

श्री आरिफ अकील -- बदुआ नहीं है. सफाया तो होना है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- जैसे नगर निगम, नगर पंचायतों, नगरपालिका के चुनाव में हुआ है.

श्री बाला बच्चन -- अभी तो मिलकर स्वाइन फ्लू को रोको.

श्री आरिफ अकील -- अभी नगर निगम में अरबों रुपये खर्च हुए हैं. आप विषय से मत भटकाओ.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया समाप्त करें.

श्री आरिफ अकील -- अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मंत्री जी को आज आप आदेशित करें. यह आपस में बैठकर ऐसी चर्चा करें, आपकी अध्यक्षता में ही आप बैठक कर लें और मध्यप्रदेश में स्वाइन फ्लू से बचने के लिये कहां कहां, कौन कौन सी दवायें उपलब्ध हैं, क्या आवश्यकता है, क्या लोगों को समझाइश देना है. प्रेस कांफ्रेंस तो आप बहुत लम्बी लम्बी करते हो. बड़े लम्बे लम्बे एड देते हो. टीवी पर बहुत सारी बातें करते हो. टीवी पर भी एक एड देना शुरू कर दोगे स्वाइन फ्लू से बचने के लिये ये उपाय हैं. इसको करो, इससे बच सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है. आज दहशत का माहौल है. जिन प्रायवेट अस्पतालों से कमीशन मिलता है, वहां पर मरीज भेज देते हो. अभी एक आदेश जारी कर दिया कि साहब प्रायवेट अस्पताल स्वाइन फ्लू का इलाज नहीं करेंगे. क्यों भैया? पैसे की कमी है, तो कटोरा लेकर बाजार में खड़े हो जाओ, पैसे मांग लो कि स्वाइन फ्लू से बचने के लिये हमारे पास पैसे नहीं हैं, दान दे दो, भीख, दक्षिणा दे दो, ताकि हम मध्यप्रदेश के लोगों का इलाज कर सकें. आपने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने फैसला, ऐलान कर दिया है कि सब प्रायवेट अस्पतालों में इलाज होगा. आपने कब सर्कुलर जारी कर दिया, किस तारीख को वह सर्कुलर जारी हुआ. कौन कौन से अस्पतालों में आपने पहुंचा दिया और उन अस्पतालों में पहुंचाने के बाद कौन कौन से अस्पतालों में कितने मरीजों के रखने के लिये कितने बेड एलाट किये गये, उसको आप बताओ. वहां कोई व्यवस्था नहीं है. अध्यक्ष जी, मंत्री जी केवल यह सोचें कि मैं सिर हिला हिलाकर ठीक कर दूंगा. तो भैया यह स्वाइन फ्लू की बीमारी है, आपके सिर हिलाने से, आपके चेहरे से नहीं जाने वाली है. इसके लिये प्रयास करना पड़ेगा. इसके लिये मेहनत करनी पड़ेगी. क्या वजह थी कि मध्यप्रदेश के मुखिया को मैदान में आना पड़ा. आप उसको देखो. मेरा आपसे कहना है कि - **सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिये.** आप इलाज की व्यवस्था करो. मध्यप्रदेश के लोगों को इलाज दो. स्वाइन फ्लू के नाम से लोग जो घबराये हुए हैं,

बैचेन, परेशान हैं, किसी को खांसी, जुकाम हो रहा है, तो परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं. उसकी उचित व्यवस्था करो. और अच्छा इलाज करोगे तो हम आपको शाबाशी देंगे. यही कहेंगे कि आप वाकेही अच्छे मुख्यमंत्री हैं. अच्छे मुख्यमंत्री होने वाले हैं. (हंसी).. क्योंकि अब कोई न कोई तो चार्ज लेगा. मेरा आपसे कहना यह है कि इस बीमारी का इलाज आप लोगों का करवायें. और अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो इस सदन के माध्यम से जो चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री जी को बतायेंगे कि ऐसे अधिकारियों को लो, जिनको खुद इलाज की जरूरत नहीं हो. जिनका इलाज हो चुका हो, जो पूरी तरीके से सोचते हों, जो लोगों का इलाज करने में सक्षम हों. ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर को दिखाकर फिर उनको इलाज कराने की आवश्यकता पड़े. अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में स्वाइन फ्लू की संक्रामक बीमारी जबरदस्त प्रदेश के सभी अंचलों में फैलती जा रही है. मैं सरकार के माननीय मंत्री जी से और सरकार में बैठे हुए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर हम प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाये, प्रदेश के लोगों को स्वस्थ नहीं रख पाये, तो मैं समझता हूं कि हम प्रदेश के विकास की और प्रदेश के स्वस्थ रहने की भी कल्पना नहीं कर सकते. जब पहले से ही यह चेतावनियां आ रही थीं, आज लगभग 100 लोग स्वाइन फ्लू की संक्रामक बीमारी से काल के गाल में समा गये हैं और यह तो वह आंकड़े हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रदेश के मेडिकल कालेज कुछ ही जगह हैं ग्वालियर, जबलपुर, इन्दौर, भोपाल लगभग 4 जगह के जो आंकड़े हैं, वह 100 मौतों की पुष्टि कर रहे हैं, अगर इसके अलावा हम देखें कि प्रदेश में कितने लोगों की मौतें सामान्य बुखार, जुकाम और खांसी के कारण हो रही है, इसका कोई रिकार्ड सरकार के पास भी नहीं है, जबकि मेरा यह मानना है कि हमारे प्रदेश की जनता में बीमारी सहन करने की शक्ति अधिक है. मौसम बदलता है, तो हल्की सी जुकाम, खांसी और बुखार हल्का सा होता है, हम सामान्यतः सहन करते हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू संक्रामक बीमारी के बारे में जिन लोगों को पता नहीं है, उन्हें तब पता लगता है कि 5-6 दिन में सहन करते-करते वह काल के गाल में चले जाते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं और उनका परीक्षण ही नहीं हो पाता, ऐसे हजारों लोग प्रदेश में हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से पहले तो यह अनुरोध करूंगा और सरकार को भी यह चिन्ता होना चाहिये कि अस्पताल में जो मौतें हो रही हैं, वह तो ठीक है कि उनकी रिपोर्टें आ रही हैं, लेकिन इन अस्पतालों के अलावा भी इस जुकाम, खांसी और बीमारी के कारण प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में ऐसी कितनी मौतें हुई हैं, इससे पता लग सकेगा कि इस स्वाइन फ्लू की बीमारी ने कितना भयंकर रूप पूरे प्रदेश में ले लिया है. स्वाइन फ्लू

एच.1, एन.1 नाम का वायरस है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच की व्यवस्था केवल एक ही लैब है जबलपुर में डी.आर.डी.ओ. में इसकी जांच हो पाती है, कहीं भी इसकी जांच की व्यवस्था नहीं है कि जिससे पता लगाया जा सके कि स्वाइन फ्लू है भी या नहीं है. प्रायमरी इलाज दिया जाता है, माननीय मंत्री जी, पहले तो आप स्वीकार करने के लिये ही तैयार नहीं थे कि स्वाइन फ्लू फ्लू से मौतें हो रही हैं, या स्वाइन फ्लू बीमारी फैल रही है. यह किसी पेपर की कटिंग है इसमें दिया हुआ है मुख्यमंत्री जी भड़के, तो स्वास्थ्य मंत्री ने माना प्रदेश में अब तक 44 मौतें. भाई, आपको मानने में क्या दिक्कत है ? प्रदेश की जनता मर रही है, प्रदेश के लोग मर रहे हैं, इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, तो कम से कम यह व्यवस्था करें कि प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में इसके चैक अप की व्यवस्था हो जाये, इसके परीक्षण की व्यवस्था हो जाये कि स्वाइन फ्लू के परीक्षण के लिये जबलपुर नहीं भेजना पड़े और उसका परीक्षण वहीं हो जाये. आपने इसकी चिन्ता करते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिलों में आयसोलेशन वार्ड बनाये, स्वाइन फ्लू का स्वयं मैं डाक्टर तो नहीं हूं, पर मैं जहां तक समझता हूं कि सर्दी, जुकाम के साथ-साथ सीधा-सीधा फेफड़ों पर असर करता है, स्वांस नली बंद होती है या स्वांस लेने में दिक्कत आने की समस्या पैदा होती है. आपने आयसोलेशन वार्ड तो बना दिये, क्या जिलों में वेंटीलेटर है ? किस तरह से आप उसकी सहायता करेंगे, किस तरह से आप उसकी रक्षा करेंगे ? आपने यह व्यवस्था नहीं की है, हम चाहते हैं कि प्रदेश में सभी जगह वेंटीलेटरों की व्यवस्था की जाये, तो कम से कम इस बीमारी से कुछ समय तक बचाया जा सके, इसके लिये राहत मिल सके. माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि लोग मेडिकल हास्पिटल में जायें, आपके प्राथमिक उपचार केन्द्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जायें. डॉ. गोविन्द सिंह ने अभी बताया और मैं भी कह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 70 परसेंट पद रिक्त पड़े हैं. मेरे यहां जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक में भी डाक्टर नहीं हैं, वहां या तो लैब टैक्निशियन होगा, या केवल ए.एन.एम. होगी और वह भी उनकी मर्जी आती है, तो हास्पिटल खोलते हैं और यदि उनकी इच्छा नहीं होती है, तो वह हास्पिटल भी नहीं खोलते, यह स्थिति पूरे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की है. इससे पहले डेंगू भी काफी बड़े रूप में फैला. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ पूरी सरकार के और माननीय मंत्री जी के तो क्या कहने ? प्रदेश के स्वास्थ्य की कितनी चिन्ता है ? अमानक दवाओं के बारे में कैग की रिपोर्ट में भी आया, मीडिया भी रोज दे रही है कि किस तरह से अमानक दवाओं को खरीद-खरीद कर यह गवर्नमेंट सप्लाई करा रहे हैं, इन्होंने जिनकी जांच की भी आवश्यकता नहीं समझी. करोड़ों रुपये की अमानक दवाई, जो कैग ने खुलासा किया है, इसमें आपको एक्शन लेना चाहिये कहीं ऐसा ही तो फिर नहीं हो कि स्वाइन फ्लू के नाम पर, महामारी वाली इस संक्रामक बीमारी को रोकने के नाम पर फिर आप ऐसी कंपनियों से दवा खरीदने का काम शुरू कर दें, जिनका परीक्षण नहीं करवा पाओ, जो अमानक स्तर की दवायें देते हैं. भोपाल के जे.पी. हास्पिटल में ही 78 लाख रुपये की अमानक दवाईयां खिला दी बिना जांच किये इसमें कम से कम यह व्यवस्था करें कि प्रदेश में कहीं भी अमानक दवाई न खरीदी जाए आप प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का खयाल करें, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं. आयुष औषधालय,

आपके जितने भी आयुर्वेदिक औषधालय हैं मैं समझता हूँ कि जिलों में लगभग सभी जगह हैं मेरा यहां पर 8 औषधालय हैं वहां पर एक भी डॉक्टर नहीं है, जब एक भी डॉक्टर नहीं है तो आप इन अस्पतालों को समाप्त कर दें तो ज्यादा बेहतर है, वहां पर ताले पड़े रहते हैं. या तो उनमें आप डॉक्टरों की व्यवस्था करें तथा प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की चिन्ता करें यही स्थिति सभी जगह है. हमारे यहां पर स्वाइन फ्लू नामक संक्रामक बीमारी के वायरस पूरे देश में फैले हुए हैं हमें देश के अन्य प्रदेशों से भी सीख लेनी चाहिये. राजस्थान जब गया मैंने देखा राजस्थान में स्वाइन फ्लू प्रतिरोधी दवा सभी जगहों पर पिलाना शुरू कर दी, उनको टीकाकरण करना शुरू कर दिया और टेमेफ्लू नामक गोली देना प्रारंभ कर दी, लेकिन इस प्रदेश की सरकार की नींद नहीं खुली और न ही खुल रही है कि स्वाइन फ्लू प्रतिरोधी दवा जब विकसित कर ली गई है तो उस दवा को पिलाने का काम करें. टीकाकरण करने का अथवा टेबलेट देने का काम सरकार क्यों नहीं कर रही है इस सरकार को चिन्ता होना चाहिये. मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर हम प्रदेश के जनता के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारा रहना बेकार है. हमें पूरी तरह से प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की चिन्ता करनी चाहिये और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के कई नौजवान, कई बच्चे इस संक्रामक बीमारी से पूरी तरह से पीड़ित हो जाते हैं तथा वे समाप्त हो जाते हैं तो उनके परिवारजनों की क्या स्थिति होती है इसकी सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिये और जो अमानक दवाएं खरीदी गई हैं, जिनके खिलाफ आपने किसी को निलंबित करने की तथा किसी के खिलाफ डी.ई. करने की तो सिफारिश की है, लेकिन उन अमानक दवाओं को खाने से जिनके लिये आपके अधिकारी जिम्मेदार हैं, आपकी नीति जिम्मेदार है, अमानक दवाईयों की सप्लाई के लिये आप विशेष रूप से जिम्मेदार हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है मैं समझता हूँ कि यह मानव, व्यक्ति के साथ मानवाधिकार का उल्लंघन कहा जाएगा इसमें आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए जिससे प्रदेश में इस तरह से अमानक दवाईयां खिलाने या प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कोई हिम्मत नहीं कर सके. माननीय अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूँ कि आपको भी इसमें चिन्ता होनी चाहिये. आप ही नहीं हमारे सभी के जिलों में यही स्थिति है जैसे मेरे जिले श्योपुर जो कि ग्वालियर से 200 से 300 किलोमीटर दूर पड़ता है. यदि वहां पर बीमार हो जाए तो तीन चार दिन वहां पर इंतजार करता है और उसके बाद में ग्वालियर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत यह हो जाती है कि हॉस्पिटल में जाने के बावजूद भी, मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बावजूद भी हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वह इतना लेट हो जाते हैं तो उनको मौत के मुंह में जाना ही पड़ता है तो पूरे प्रदेश के जनता के स्वास्थ्य की हम सबको मिलकर के चिन्ता करना चाहिए. हम चाहते हैं कि अगर आपके पास में फंड नहीं है, जैसा कि आपने कहा हम चाहते हैं कि पूरे विधायकों की विधान सभा क्षेत्र विकास निधि एक बार ले लें, लेकिन प्रदेश की जनता को स्वाइन फ्लू की वजह से मौत के मुंह में जाने से बचाने का प्रयास यह सरकार करेगी तो हमें खुशी होगी और पूरे प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की चिन्ता यह सरकार करेगी और करना चाहिये. आप और हम भोपाल में बैठे हैं भोपाल के हॉस्पिटल की रोज़ रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं इस बात को विशेष रूप से

जरूर निवेदन करूंगा तथा आपसे भी आग्रह करूंगा कि सरकार को यह निर्देश दें कि सरकार मेडिकल कॉलेजों में मृत्यु के अलावा पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में, दूरस्थ अंचलों में सर्दी, जुकाम, खांसी से कितने लोगों की मौते हुई हैं, इसका भी आप सर्वे करवा लें तो प्रदेश का खुलासा हो जाएगा. मैं समझता हूं कि यह मौतें हजारों से ऊपर होंगी और मैं कहीं से भी गलत नहीं हूं, सरकार को यह करना चाहिये तथा इस बीमारी से लड़ने के लिये पूरी तरह से सरकार को आगे आना चाहिये और इसमें छिपाने या संकोच करने की कोई बात, माननीय मंत्री जी नहीं होना चाहिये. आप कह रहे हैं कि स्वाइन फ्लू फैला ही नहीं है मुख्यमंत्री जी जब डांट रहे हैं तब कहीं आप स्वीकार कर रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि महामारी का रूप ले चुकी इस संक्रामक बीमारी स्वाइन फ्लू के वायरस को रोकने के प्रति आप और हम सभी को चिन्ता करना चाहिये आपने इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य किया इसके लिये आपको धन्यवाद.

श्री मुकेश नायक(पर्वी) – माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया. पिछले तीन महीनों में हमने डेंगू और स्वाइन फ्लू दो बीमारियों का प्रकोप मध्यप्रदेश में देखा और मैं बड़े दुख के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं कि दोनों बार ब्यूरोक्रेसी का इतना बड़ा फेल्युअर है कि क्षमा करने योग्य नहीं है. मैं मंत्री महोदय को इसलिये इसमें दोषी मानता हूं कि उनके डिपार्टमेंट के अंदर जो अधिकारी हैं उनके ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं है कोई समन्वय नहीं है और विषयों को लेकर, नीतियों को लेकर, समस्याओं को लेकर कोई संवाद और ठीक से कनेक्टिविटी अधिकारियों के बीच नहीं है और उसका परिणाम मध्यप्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है. अभी चर्चा चल रही है वैक्सीन की. कहां पर उसका टेस्ट होता है ? आज केंद्र सरकार ने यह निर्देश पूरे देश के लिये जारी किया है कि इसके परीक्षण के लिये पैसे ज्यादा लिये जा रहे हैं. 4500 रुपये से ज्यादा इसकी फीस न ली जाये. जब मध्यप्रदेश में डेंगू आया तो आपके अधिकारियों ने मीटिंग लेकर कहा कि जब तक 10 हजार प्लेटलेट्स न आ जायें तब तक अतिरिक्त प्लेटलेट्स लोगों को लगाने की आवश्यकता नहीं है. टेक्निकली तो यह बात बिल्कुल ठीक जान पड़ती है. लेकिन आम तौर पर मेडिकल साइंस में जो डाक्टर कहते हैं कि अगर 30 हजार तक, 50 हजार तक, प्लेटलेट्स आ जायें तो ब्लड बैंक से प्लेटलेट्स मंगाकर मरीजों को देना जरूरी है. नहीं तो कभी भी कमजोर इम्युनिटी वाला, कमजोर प्रतिरोधात्मक शक्ति वाला मरीज कभी भी कोलेप्स हो

सकता है. कभी भी मर सकता है. सुनिये माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में क्या हो रहा है. मध्यप्रदेश में ब्लड बैंक नहीं हैं. यहां पर अधिकारी भी बैठे हैं. मंत्री जी भी बैठे हैं. माननीय मंत्री जी, आप अपने अधिकारियों से पूछकर यह बताएं कि मध्यप्रदेश में कितने ब्लड बैंक हैं जिसमें ब्लड के सात घटक जिसमें प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, प्रोटीन आदि-आदि को अलग-अलग करने की क्षमता है. जो व्यक्ति रक्तदान करता है वह पूरी की पूरी बोतल वैसी ही मरीज को चढ़ा देते हैं और अत्यंत दुर्भाग्य के साथ मुझे मध्यप्रदेश की विधान सभा को अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह बताना पड़ रहा है कि रेड क्रॉस का जो ब्लड सेपरेशन की मशीन लगाने का लाईसेंस है. गंभीर विषय है स्वाईन फ्लू की जो मैं जो चर्चा कर रहा हूं अगर यह चर्चा सार्थक रूप से इस विधान सभा में हो पायी जिसके लिये यह सदन बना है....

अध्यक्ष महोदय – आप एक मिनट में अपनी बात कह लें.

श्री मुकेश नायक - माननीय अध्यक्ष महोदय, दो साल तक मध्यप्रदेश के रेडक्रॉस के ब्लड बैंक की परमीशन इन अधिकारियों ने नहीं होने दी, कामा नहीं है, फुल स्टाप नहीं है. औपचारिकताओं की कमी बताकर धंधेबाज ब्लड बैंकों को, प्रायवेट ब्लड बैंकों को, इन्होंने अनुमति दे दी. रेड क्रॉस के ब्लड बैंक की इन्होंने अनुमति नहीं दी क्योंकि वह फाईल मंत्री तक आती नहीं है अधिकारियों तक सीमित थी. वह यह उम्मीद करते थे कि जो रेडक्रॉस सोसायटी है वह उनको पैसे दे तब वे लाईसेंस जारी करें. ऐसी मानव विरोधी ब्यूरोक्रेसी जो आज स्वास्थ्य विभाग में बैठी है. इसको जितनी सजा दी जाये कम है.

अध्यक्ष महोदय – आप समाप्त करें.

श्री रामनिवास रावत – मुकेश भाई ब्यूरोक्रेसी किससे चलती है. ब्यूरोक्रेसी कौन चलाता है तब चलती है.

अध्यक्ष महोदय – कृपया समाप्त करें.

श्री मुकेश नायक – आपकी बड़ी कृपा होगी. थोड़ा समय दे दें. मैं एक महीने से इस विषय पर तैयारी कर रहा हूं. अगर मैं नहीं बोल पाऊंगा तो मुझे दुख होगा.

अध्यक्ष महोदय – आपका स्थगन प्रस्ताव तो अभी आया मैंने आपको अनुमति दे दी. आपने इस विषय पर स्थगन दिया नहीं था. जब यह चर्चा प्रारंभ हो गयी तब आपने इसको यहां दिया तो इसलिये आपको मैंने बहुत समय दे दिया. चलिये एक मिनट और ले लीजिये.

श्री मुकेश नायक - अध्यक्ष महोदय, अगर आपको लगे कि जो चर्चा मैं कर रहा हूं यह स्थगन प्रस्ताव से प्रासंगिक है और जरूरी है तो आप मुझे समय दे दें नहीं तो मैं अभी बैठ जाता हूं

अध्यक्ष महोदय - एक मिनट में बोल दीजिये.

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री(कुं.विजय शाह) – अध्यक्ष महोदय, इनका नाम ही नहीं था यह तो आपकी कृपा से बोल रहे हैं. मेरा निवेदन है विषय से न भटके.

श्री मुकेश नायक - अध्यक्ष महोदय की कृपा से ही तो सदन चलता है. एक टामीफ्लू वेक्सीन की चर्चा हो रही है. यह बहुत कम लोग जानते हैं कि इस वेक्सीन के कारण बहुत प्रकार के न्यूरोलोजिकल डिसऑर्डर की कंप्लेंट आई हैं. बहुत कम लोग जानते हैं. सिरदर्द होता है और दिमाग पर ऐसा गहरा असर होता है कि एक परमानेंट क्षति इससे पहुंचती है और इस वैक्सीन को बहुत भारी प्रचार करके धंधेबाज लोग बेईमान लोग पूरे देश में महंगे दामों में बेच रहे हैं और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी नौकरशाही और पूरे ऐसे लोग शामिल है, आगे चलकर पूरे देश में इसका भंडाफोड होगा, पूरे देश के लोग जानेगे कि किस तरह का यह अमानवीय कृत्य हो रहा है ..

श्री जसवंत सिंह हाड़ा:- माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई घटना से जोड़कर बता रहे हैं कि कहानी सुना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं इसके कोई प्रमाण नहीं है।

श्री जसवंत सिंह हाड़ा:- कहानी नहीं है, जो चीज हम नहीं जानते वह आप बता रहे हैं।

श्री मुकेश नायक :- यह कोई जरूरी है कि जो आप नहीं जानते वह हम नहीं जाने, आप प्रदेश में किसी भी मरीज की प्रासंगिक घटना बताईये न। (व्यवधान) आप पढ़ेंगे लिखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय इस तरह के मानव विरोधी व्यवहार के कारण और मुझे नहीं बोलने देने के कारण इस गंभीर विषय पर मैं बोल नहीं पाया इसका मुझे दुख है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो बीच बीच में बोल रहे हैं, ये अपने मनुष्य विरोधी रवैये को त्याग रहे हैं..

अध्यक्ष महोदय :- आपको बोलने का बहुत समय दिया, आपने अपना प्रस्ताव नहीं दिया था, इसके बाद भी आपको बोलने की अनुमति दी।

श्री बाला बच्चन (पानसेमल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे स्वाइन फ्लू पर बोलने का समय दिया। वर्षाकाल में डेंगू का प्रकोप प्रदेश में बढ़ा और उसके कारण कई मौतें हुईं लेकिन तब भी सरकार नहीं चेती और अब जहां तक मेरी जानकारी है कि पूरा प्रदेश स्वाइन फ्लू की जकड़ में और स्वाइन फ्लू ने पूरे प्रदेश में और हमारे जिले बड़वानी में भी स्वाइन फ्लू से मौत हुई है। अकेले इंदौर शहर में स्वाइन फ्लू में 62 लोगों की मौत हो चुकी है यह आंकड़ें कल तक हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पिछली तीन या चार कैबिनेट बैठकों में से एक भी बैठक में स्वाइन फ्लू को किस तरह से प्रदेश में रोका जाए, उस पर चर्चा नहीं की गई है। मंत्री जी का आंकड़ा आता है कि 77 लोगों की मौत हुई है, पीएस हेल्थ का आंकड़ा आता है कि 48 लोगों की मौत हुई। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद बात आती है कि स्वाइन फ्लू से संबंधित बीमारी की जांच होना है, जो लेब में जांच के लिये कैसे जाते हैं, उसमें पीएस हेल्थ का बयान है कि 48 जांच हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जब हाईकोर्ट तलब करती है तो उसमें पांच या छः का आंकड़ा बताते हैं तो पहले सरकार अपने आप में सही जवाब दे, उसके बाद जो इतने लोग मर चुके हैं और यह बीमारी आगे न बढ़ पाये इसके रोकथाम के लिये जो आपके पास मुझे नहीं लगता है कि अस्पताल में दवाई है और उसके बाद आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ है। अभी तक जो प्राइवेट

अस्पताल थे उन अस्पतालों में मरीजों को भरती के लिये प्रतिबंध लगा रखा था, मैंने खुद एक केस में मेरी विधानसभा का एक बहादुर भाई करके है लुहारा गांव का, मैंने इंदौर के कई अस्पतालों में फोन किया उनको भर्ती नहीं किया जा रहा था लेकिन मैं उनकी बाद में मौत हो गई। मैं यह कहना चाह रहा था कि आपने एक तो प्रतिबंध अभी हटाया है और हेल्थ डिपार्टमेंट ने यह काम किया है कि जो नर्सिंगहोम हैं वहां अगर स्वाइन फ्लू से संबंधित मरीजों को भर्ती करोगे और ईलाज करोगे तो हम तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। यहां तक का आर्डर इन्होंने निकाला है।

श्री मुकेश नायक :- लाइसेंस कैंसिल किया है, करेंगे नहीं। (XX)

अध्यक्ष महोदय :- यह कार्यवाही से निकाल दें।

श्री शरद जैन :- अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार (XX) इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। हम तो इनको समझदार समझते रहे।

अध्यक्ष महोदय :- कार्यवाही से निकाल दिया है। (व्यवधान)

श्री कमलेश्वर पटेल :- :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार तो पिटवा रही है कल पूरा प्रदेश बंद था। पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी थी। सरकार तो उन्हें पिटवा रही है।

श्री बाला बच्चन :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में डेंगू, स्वाइन फ्लू या अन्य जो बीमारियां या महामारियां जो फैलती हैं, इसकी पहले से शासन को रोकथाम करनी चाहिये और आपने इस संक्रामक बीमारी में आपने विधान सभा में चर्चा के लिये जो समय दिया और जो लिया है, मेरे दिल की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और विनती करता हूं कि आप अपने और स्वास्थ्य विभाग की जिन कमियों के कारण डेंगू बढ़ा और स्वाइन फ्लू जो बढ़ रहा है, अपने पैर पसारता जा रहा है इस बीमारी से और लोग अस्वस्थ न हों, बच सकें इसके लिये सरकार पुख्ता इंतजाम करे। मैं ऐसी पुख्ता व्यवस्था चाहता हूं ताकि इस बीमारी पर नियंत्रण हो सके, सभी अस्पतालों में पर्याप्त इलाज हो सके। मरीज की जांच नहीं हो पाती है कि उसे कौन सी बीमारी है तब तक उसकी मौत हो जाती है

मंत्रीजी आपको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और विभाग को इसके लिए हिदायत देना चाहिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को इन बीमारियों पर नियंत्रण करना चाहिए यह मेरा आपके माध्यम से उनसे आग्रह है.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर विषय पर सम्मानित सदस्य गोविंद सिंह जी, जनाब आरिफ अकील साहब, आदरणीय रामनिवास रावत जी, आदरणीय मुकेश नायक जी व आदरणीय बाला बच्चन साहब ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की है.

वास्तव में प्रदेश इस समय इस प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है. मुख्य सचेतक जी प्राकृतिक आपदा में इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि यह हिन्दुस्तान के बीस राज्यों में है यह सिर्फ मध्यप्रदेश में नहीं है, अभी राजस्थान का आप ही ने जिक्र किया था कि वहां पर सर्वाधिक मौतें हुई हैं इसलिए यह प्राकृतिक आपदा है यह पूरे देश पर है सिर्फ मध्यप्रदेश पर ही नहीं है. फरवरी के अन्त में जब सर्दी का मौसम जाता था और गर्मी का मौसम आने को होता था उस समय वर्ष 2009 से यह समस्या लगातार आ रही थी इसलिए सरकार ने बहुत पहले ही अर्थात् 15.11.2014 से ही इसकी बैठकें लेना प्रारंभ कर दिया था. आदरणीय गोविन्द सिंह जी व आरिफ भाई ने कहा कि दवाइयां नहीं थीं या दवाइयां नहीं मिल रही हैं. हम एडवांस में 8 हजार गोलियां प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचा चुके थे और इस बीमारी के आने के पहले लगभग 12 हजार गोलियां हमारे पास स्पेयर में थीं इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कह सकता हूँ कि जिले में ऐसा कोई अस्पताल नहीं था जहां हमने दवाइयों की व्यवस्था न की हो.

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि यह बीमारी ऐसी है जो कि भ्रम पैदा करती है यह सर्दी-जुकाम से मिलती-जुलती बीमारी है लोग प्रारंभ के दिनों में इसको सर्दी-जुकाम समझ लेते हैं बस वहीं ठुटि हो जाती है अगर वहां ठुटि न हो और लोग तात्कालिक रूप से अस्पताल में आकर उसकी जांच करा लें या डॉक्टर को दिखा लें तो डॉक्टर देखते ही लगभग उसे समझ जाते हैं

और वे उसकी जांच करा देते हैं तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है और बहुत सस्ती इसकी दवाई है दिन में दो बार लेने की दवाई है और इससे मरीज ठीक हो जाते हैं मध्यप्रदेश में ऐसे सैकड़ों मरीज अस्पतालों से ठीक होकर गए भी हैं. इसके लिए हमने पहले से एहतियात रखी थी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया कि विज्ञापन पर हजारों रुपया खर्च कर दिया गया. यह जरूरी था क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि यह भ्रम पैदा करने वाली बीमारी है इसमें जन-जागरण की आवश्यकता बहुत जरूरी है लोगों में जो भ्रम फैलता है इस बीमारी को लेकर, इसकी सावधानियों को लेकर, क्या-क्या आपको महसूस हो जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो, गले में फांसे उठें तो इसे साधारण सर्दी-जुकाम न समझें और अस्पताल में आएं. इसके लिए प्रचार-प्रसार की भी जरूरत थी ताकि यह भ्रम दूर हो सके इस भ्रम को दूर करने के लिए हमको विज्ञापनों की भी जरूरत थी.

डॉ.गोविन्द सिंह-- फोटो लगवाना भी जरूरी था.

वन मंत्री (डॉ.गौरीशंकर शेजवार)-- मतलब आपके जमाने में फोटो का प्रचलन था नहीं और आपने इतनी सफलता कभी की नहीं अब नरोत्तम जी ने कितनी अच्छी बातें बताईं तो हमें कुछ धरातल पर आना चाहिए कि फोटो पर ही चिढ़ रहे हों. क्या मतलब है.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो नागौद हॉस्पिटल में टिटनेस का इंजेक्शन नहीं था. मंत्री जी बोल रहे हैं कि पूरे अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध हैं.

श्री कमलेश्वर पटेल-- कौनसे जिले में बाँटीं यही पता नहीं.

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (कुंवर विजय शाह)-- स्वाइन फ्लू में टिटनेस नहीं लगता.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- अध्यक्ष महोदय, नागौद हॉस्पिटल सामुदायिक केन्द्र में टिटनेस का इंजेक्शन नहीं था. आप लोग जबर्दस्ती क्यों असत्य बोल रहे हैं. अभी आपके जो हैं प्रवीर कृष्ण साहब पी एस साहब, आधे डॉक्टर तो इन्होंने सस्पेंड कर दिए.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जाएँ.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- इनका खुद ही लगता है दिमाग खराब है. 6 महीने...

अध्यक्ष महोदय-- इसको कार्यवाही से निकाल दें.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- असत्य बोल रहे हैं मैं कह रहा हूँ टिटनेस का इंजेक्शन 24 तारीख को...

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी, आप अपनी बात रखें.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- मैंने अपने पैसे से मंगवाया था.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जाएँ. मंत्री जी, आप अपनी बात जारी रखें...(व्यवधान)..

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रमुख सचिव पूर्णतः स्वस्थ हैं.(व्यवधान)..

कुंवर विजय शाह-- दिमाग की भी जाँच करा लेते हैं.

श्री आरिफ अकील-- कब जाँच हुई थी और कौनसे डॉक्टर ने की थी...(व्यवधान)..

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- जाँच की आरिफ भाई जब बीमार हुए थे...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जाएँ गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है...(व्यवधान)..बैठ जाएँ.

माननीय मंत्री जी अपनी चर्चा जारी रखें...(व्यवधान)..

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन(श्री लाल सिंह आर्य)-- ऐसे पी एस हैं पूरे मध्यप्रदेश में प्रवास कर रहे हैं...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जाएँ गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है...(व्यवधान)..

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- माननीय अध्यक्ष जी, वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं. पूरी तरह से एक्टिव हैं.

श्री मुकेश नायक-- अध्यक्ष महोदय, यही तो हम जानना चाहते हैं कि यह जाँच में कब पता लगा.

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- मुकेश भाई, जाँच तब होती है जब कोई अस्वस्थ हो...(व्यवधान)..स्वस्थ व्यक्ति की जाँच नहीं होती...(व्यवधान)..

श्री आरिफ अकील-- हम इस सदन में कह रहे हैं कि वे अस्वस्थ हैं...(व्यवधान)..

श्री मुकेश नायक-- कोई आदमी स्वस्थ है इसकी क्या परिभाषा है. बीमारी की परिभाषा होती है स्वस्थ की क्या परिभाषा है.

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- अध्यक्ष महोदय, इतने एक्टिव हैं कि डेंगू आया तो फूलों का पानी निकालते हुए एक एक...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जाइये...(व्यवधान)..

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- आज भी सबसे ज्यादा प्रवास करने वाले हमारे प्रमुख सचिव हैं.

श्री बाला बच्चन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने बोला यह बात सही होती देखी. दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वे भागे हैं. इन्दौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी और भोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से...

अध्यक्ष महोदय-- इसको कार्यवाही से निकाल दें. माननीय मंत्री जी कृपया अपनी बात जारी रखें और कृपया कोई भी व्यवधान न करें.

श्री बाला बच्चन-- इसलिए जो बात माननीय विधायक जी ने उठाई है....

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएँ...(व्यवधान)..यह बात ठीक नहीं है...(व्यवधान)..आप माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनें...(व्यवधान)..आपने स्वयं प्रस्ताव उठाया है.

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह)-- माननीय अध्यक्ष जी, स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर मसले पर यह व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाकर क्यों आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर जब बात हो रही है, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप उसको हल्का क्यों कर रहे हैं...(व्यवधान).

श्री यादवेन्द्र सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एक टिटनेस का इंजेक्शन नहीं है....

अध्यक्ष महोदय—यादवेन्द्र सिंह जी, आपकी बात हो गई अब आप कृपया बैठ जाएँ..
(व्यवधान)..

श्री यादवेन्द्र सिंह-- इनकी बात मानें, सुनें.

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाएँ. उत्तर तो सुन लें.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- जब आपके यहाँ टिटनेस का इंजेक्शन नहीं है...

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- इसमें टिटनेस नहीं लगता दादा.

अध्यक्ष महोदय-- यादवेन्द्र सिंह जी, अब आपकी बात गई रिकार्ड में. अब आप बैठ जाइये.

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- इसमें टिटनेस कहाँ से आ गया...(व्यवधान)..

श्री कमलेश्वर पटेल-- टिटनेस से मतलब नहीं है. मतलब स्वास्थ्य की व्यवस्था से है जब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में टिटनेस का इंजेक्शन नहीं है तो स्वाइन फ्लू की दवाई कहाँ से होगी....
(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय-- बैठ जाइये यह कोई विषय नहीं है. आप लोगों को उत्तर सुनना है कि नहीं सुनना है.

डॉ.गोविन्द सिंह-- माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की जवाबदारी पहले होती है, अधिकारी की बाद में. कई जगह ठीक काम भी किया है.

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी, बोलिए.

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- माननीय अध्यक्ष महोदय, उपनेता आदरणीय बाला बच्चन जी ने वह बात कही. मैं थोड़ा उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ. मैं स्वयं बहुत ज्यादा सम्मान मीडिया का करता हूँ. हम कभी प्रेस से भागे नहीं हैं. मैं हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता हूँ. हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता हूँ. आप ही के सदस्य अभी कह रहे थे कभी हम भागे नहीं हैं. हम मानते हैं कि वे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और उनके माध्यम से ही सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता को मिलती है और जनता की समस्याओं की जानकारी सरकार को मिलती है.

श्री बाला बच्चन-- माननीय मंत्री जी, मैंने अगर बोला है तो इस बात की आप पुष्टि करें को भोपाल और इन्दौर दोनों जगह....

अध्यक्ष महोदय-- माननीय बाला बच्चन जी, अब इस पर डिबेट न करें.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, मैं चाह रहा था कि आरिफ अकील जी, गोविंद सिंह जी और मुकेश जी ने जो सवाल किये हैं मैं उन सबके एक-एक करके जवाब दूँ लेकिन मैं सीधा विषय पर आ जाता हूँ. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में 71 स्क्रीनिंग सेंटर हमने स्वाइन फ्लू की आहट के साथ ही प्रारंभ कर दिये थे और 50 हजार लोगों की स्क्रीनिंग इस स्क्रीनिंग सेंटर में हमने की और जहाँ तक स्वाइन फ्लू की जांच की लेबोरेटरी की बात आई थी, यह हाई सिक्युरिटी में ईजी रहती है क्योंकि वायरस अगर कहीं से निकलकर बाहर आ गया तो एक नई समस्या उस शहर के लिए खड़ी हो जाएगी इसलिए हिंदुस्तान में इस तरह की कुल 8 लेबोरेट्री हैं उन 8 में से 2 मध्यप्रदेश के अंदर हैं एक जबलपुर में , एक ग्वालियर में है और हम बहुत जल्दी इन्दौर और भोपाल में भी इस लेबोरेट्री को लाने के बारे में विचार कर रहे हैं और लेकर आएंगे. जिस तरह से प्रदेश के अंदर यह लेबोरेट्री आ जाएंगी सभी जगह पर, चूंकि उसकी हाई सिक्युरिटी जोन होती है और जहाँ तक मुकेश जी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 4500 रुपये जांच का कहा है ,मध्यप्रदेश में कोई पैसा जांच के लिए कहीं भी नहीं लग रहा है, एक पैसा कहीं नहीं लिया जा रहा है इतनी सारी जांचें हो गई हैं एक पैसा किसी से नहीं लिया गया .कहीं कोई दवाई के लिए पैसा नहीं लिया गया, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी डे-टु-डे इसकी मॉनीटरिंग करते हैं हमारे सी.एस. और पी.एस. करते हैं, मैं स्वयं करता हूँ. अध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति मरे, एक व्यक्ति की भी मौत बहुत दुखद होती है और इसलिए पूरी संवेदना के साथ में सरकार पूरी ताकत के साथ में आगे आई और हर जगह पर, सरकारी अस्पतालों में ही निःशुल्क नहीं बल्कि प्राइवेट चिकित्सालयों को भी हमने 67 से अधिक इस मध्यप्रदेश में चिह्नित किये हैं और यह सारे 67 अस्पताल वह हैं जिनमें वेंटीलेटर की सुविधा है और जहाँ वेंटीलेटर की आवश्यकता है उसके लिए चिरायु जैसे मेडीकल कालेजेस ने आगे आकर कहा कि हम उस जगह पर

भेजने के लिए तैयार हैं, देने को तैयार हैं और हमने पूरी तत्परता के साथ में, सजगता के साथ में हर प्राइवेट चिकित्सालय में जो मेडीकल कॉलेज थे, जो हमने 67 चिह्नित किये वह, हमारे सरकारी अस्पताल थे, हर जिला स्तर पर. इस मध्यप्रदेश के अंदर पूरी मुस्तैदी के साथ में हमने काम किया. अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि यह प्राकृतिक आपदा है इसमें हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा तब ही इस प्राकृतिक प्रकोप से हम इस प्रदेश की जनता को बचा सकते हैं और इसीलिए हमने यह जो दवा है, अभी तक हमने आगामी ऑर्डर दे रखा है भविष्य के लिए कि हमारे यहाँ 1 लाख 12 हजार गोली हमेशा स्पेयर में रहे कि अगर कभी भी हमको जरूरत पड़ती है तो हम इन सबको वितरित कर दें और जितने भी हमारे पेशेंट चिह्नित हुए उन सबकी भी डे-टु-डे हम चिंता कर रहे हैं और अभी 1054 मरीज हमारे पास में और चिह्नित हैं जिनकी हम डे-टु-डे हम मॉनीटरिंग कर रहे हैं और इन 1054 में से गंभीर किस्म के अब सिर्फ पांच-सात पेशेंट ही बचे हैं. निश्चित रूप से स्थिति हमारे नियंत्रण में आती जा रही है हमने कल भी देखा, कल हमको काफी अच्छी खबरें आई, परसों भी काफी अच्छी खबरें आई, इसके पहले तक स्थिति वास्तव में काफी चिंताजनक-सी लग रही थी लेकिन हमने चिंता की तो धीरे-धीरे हमको अब इस समस्या से निजात मिल रही है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक रामनिवास जी ने कहा था वह विषय से बाहर की बात जरूर थी पर मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है हम मना नहीं कर रहे हैं. पर हमने अपने हर अस्पताल पर ए.एन.एम के द्वारा, नर्सों के द्वारा, आशा के द्वारा इस तरह का लिंक-अप किया हुआ है. हमने 70 हजार सिम वितरित की है कि अगर छोटी-सी भी कोई जानकारी प्रदेश में इस तरह की आती है तो उसका सीधा कनेक्शन भोपाल में है. हमने भोपाल के अंदर एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया है. आप कभी भी स्वाइन फ्लू के सेंटर के कॉल लगाकर देख लें. अभी टी.वी. पर भी अकस्मात कॉल लगाकर देखा गया था और रात के समय भी कॉल सेंटर में कॉल उठाया गया था मैं उस समय वह सीधा संवाद देख रहा था, यह देखकर अच्छा लगा. हमने मध्यप्रदेश के अंदर इस तरह की व्यवस्था की है और हमारे अंतिम चरण में 1271 डॉक्टर आ गये हैं.

यह बात सच है कि हमारे पास उतने डॉक्टर्स की उपलब्धता आज नहीं है जितनी हम चाहते हैं लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि अन्य उपकरणों के माध्यम से, यह भी आपको मानना पड़ेगा कि 4 लाख लोग रोज निःशुल्क दवाई इस प्रदेश में ले रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत--- अमानक दवाईयों के संबंध में आपका क्या कहना है?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी विश्वसनीयता के साथ कह सकता हूँ कि हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना जब से प्रारम्भ की है तब से एक भी दवा हमारी नकली नहीं पायी गयी है, पूरे विश्वसनीयता के साथ मैं इस सदन के सामने, आपके सामने, आपको साक्षी मानकर के कहता हूँ. मैंने हमेशा कहा है और आज भी कह रहा हूँ.

श्री राम निवास रावत-- कैग की रिपोर्ट क्या असत्य है?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- जो आपने उल्लेख किया, वह 4 साल पहले की है. यह पढ़ लें, या अभी पढ़ के सुना दें. पूरा सदन इससे अवगत हो जाएगा, मैं बैठ जाता हूँ.

श्री बाला बच्चन-- तो 4 साल पहले भी तो आपकी ही सरकार थी.यही मुख्यमंत्री थे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- जो चार साल पहले थी उस पर कार्यवाही हुई और चार साल पहले वाले मामले कोर्ट में भी पहुंच गये.

श्री राम निवास रावत-- चार साल पहले तो मुख्यमंत्री के पास चिकित्सा शिक्षा विभाग था.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- किसके पास था, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, पर जो दोषी थे वे दण्डित हुए, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ. कोई भी गलत काम करेगा, वह दण्डित होगा, वह बचेगा नहीं, इस सरकार में प्रदेश में कानून का राज है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- मुख्यमंत्री जी भी दण्डित होंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- आप चिन्ता अपनी करो, जनता आपको कितना दण्डित कर रही है, आप उसके बाद भी नहीं चेते.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- आपने विश्वास के साथ यह बात सदन में कही है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- इनके पिताजी यहां पर सदन ठीक कैसे चले, इसकी चिन्ता में रहते थे और ये इस बात की चिन्ता में रहते हैं कि सदन कैसे नहीं चले. एकदम विरोधाभासी पिता पुत्र कैसे हो सकते हैं, मैं बहुत गंभीरता से सोच रहा हूँ.

श्री यादवेन्द सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि आप कह रहे हैं कि हमारे एमबीबीएस डाक्टर नहीं हैं, अस्पताल खाली हैं तो मेरा सुझाव है कि जो बीडीएस के डाक्टर हैं जो कई हजार बेरोजगार घूम रहे हैं. वे तीन साल तो एमबीबीएस और बीडीएस के लड़के एक जैसी पढ़ाती करते हैं तो आप उन बीडीएस के बेरोजगार लड़कों को नियुक्त करके 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग कराकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भेज दें तो झोला छाप डाक्टरों से ठीक दवाई होगी,

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अध्यक्ष जी, जो स्वाइन फ्लू के मरीज रिमोट एरिया में पाये जाते हैं मान लीजिए सीधी में, रीवा में है वह भोपाल या जबलपुर आना चाहते हैं उनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती है, वे ट्रेन में आते हैं या बसों में आते हैं, गरीब लोग हैं, प्रायवेट टैक्सी नहीं कर सकते हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- यह शिवराज सिंह जी की सरकार है. उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. उनका इलाज रीवा में होगा, कोई भी दिक्कत आयेगी तो हमारी जिम्मेदारी है वे जो सुविधा चाहते हैं हम उनको रीवा में उपलब्ध करायेंगे, जबलपुर में उपलब्ध करायेंगे और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है. माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी डे टू डे मॉनीटरिंग कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, निःशुल्क दवा की, निःशुल्क जांच की सारी व्यवस्था सरकार कर रही है, यही मेरा आपसे निवेदन है.

12.39 बजे

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय-- निम्न माननीय सदस्यों की सूचनाएँ सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी--

1. श्री अजय सिंह
2. डॉ. गोविन्द सिंह
3. श्री आरिफ अकील
4. डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
5. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
6. श्री राम निवास रावत
7. श्री सुदर्शन गुप्ता(आर्य)
8. श्री दिलीप सिंह शेखावत

बहिर्गमन

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा स्वाइन फ्लू के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन

प्रस्ताव पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं इसलिए सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर हमारा दल बहिर्गमन करता है.

(नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा प्रदेश के अनेक जिलों में स्वाइन फ्लू के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) मध्यप्रदेश वित्त निगम का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, द स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन्स एक्ट, 1951 की धारा-37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14 पटल पर रखता हूँ.

(2) मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 11 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं

हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2013-14

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (कुँवर विजय शाह) - अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, एक्ट 1962 की धारा-31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 11 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2013-14 पटल पर रखता हूँ.

(3) मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक में

गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री (श्री अंतर सिंह आर्य) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा-13 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक में गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन पटल पर रखता हूँ.

दिसम्बर, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल

पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय -- दिसम्बर, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन भाग-1 एवं भाग-2 पटल पर रखा गया.

नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2014 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा

उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय -- नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2014 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाएं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखा गया.

राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय -- विधान सभा के विगत सत्र में पारित 12 विधेयकों को माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जाएंगे.

चल-अचल संपत्तियों का विवरण

श्री जयंत मलैया -- अध्यक्ष महोदय, मैं, स्वयं और अपने परिवार का वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 का चल-अचल संपत्तियों का विवरण पटल पर रखता हूँ.

12.42 बजे**ध्यानाकर्षण सूचना**

(1) प्रदेश के अनेक जिलों में यूरिया खाद की कमी से उत्पन्न स्थिति

डॉ. गोविंद सिंह (लहार), (सर्वश्री अजय सिंह, आरिफ अकील) -- माननीय अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

प्रदेश में 30 से ज्यादा जिलों में यूरिया की कमी के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूरिया की बिक्री में अव्यवस्था और कालाबाजारी से त्रस्त किसान सोसायटियों के बाहर कतार लगाकर रात-दिन बैठे रहे और एक-एक बोरी के लिए उन्हें मशक्कत करना पड़ी। जबलपुर में 19 जनवरी, 2015 को किसानों द्वारा कृषि उपज मंडी में प्रदर्शन किया तथा दो घंटे से अधिक समय तक मंडी का गेट बंद रखा गया। विजय नगर स्थित कृषि उपज मंडी के खाद्य वितरण केन्द्र में पर्चियां कटने के बाद भी किसानों को यूरिया नहीं मिला। खरगौन में किसानों ने कालाबाजारी से 450/- रुपये और बड़वानी में 530/- तथा झाबुआ में 500/- से 600/- रुपये तक यूरिया खाद खरीदी।

इसी प्रकार जिला सहकारी बैंक दतिया, ग्वालियर, मुरैना, गुना, जबलपुर, रायसेन, विदिशा, भोपाल के प्राथमिक सहकारी साख समितियों के माध्यम से कृषकों को रसायनिक उर्वरकों की मांग अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही है इस संबंध में मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव सहकारिता द्वारा विस्तृत समीक्षा की जाकर त्वरित कार्यवाही हेतु पत्र क्रमांक विप./उर्वरक/2057 भोपाल दिनांक 19.11.14 के तहत निर्देशित किया गया और प्रदेश के किसानों को खाद की पूर्ति 12 लाख मैट्रिक टन यूरिया की आंकी गई थी जो वर्तमान स्थिति में मात्र 3 लाख 20 हजार मिट्रिक टन यूरिया प्रदेश को मिल पाया है जिस कारण किसान खरीदी केन्द्रों पर लम्बी लम्बी लाइन में लगकर धक्का मुक्की से दो-चार होकर खाद लेने का प्रयास करते हैं और कई खरीदी केन्द्रों के दलाल यूरिया की खुले आम कालाबाजारी कर रहे हैं और किसान अधिक कीमत में खाद लेने को मजबूर हैं। किसानों को खाद समय पर व अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं मिल पा रही है। अधिकारी बिचौलियों से मिले हुए हैं जिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है वे मजबूरीबश यूरिया ट्रक रोककर लूटपाट कर रहे हैं। जब प्रदेश शासन के पास पर्याप्त खाद उपलब्ध ही नहीं है तो किसानों को कहां से खाद उपलब्ध कराया जायेगा? इस प्रकार शासन की घोषणा मात्र छलावा साबित हो रही है, जिससे किसानों में शासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

सहकारिता मंत्री (श्री गोपाल भार्गव)-अध्यक्ष महोदय,

यह कथन सही नहीं है कि प्रदेश में 30 से ज्यादा जिलों में यूरिया की कमी के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वास्तविक यह है कि रबी 2014-15 में दिनांक 01.10.2014 से 31.03.2015 के लिये 12.50 लाख मे. टन यूरिया भण्डारण के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। जिसके विरुद्ध दिनांक 16.02.2015 तक 12.10 लाख मे.टन यूरिया का भण्डारण कराया जाकर 11.15 लाख मे. टन यूरिया का वितरण किया जा चुका है। दिनांक 16.02.2015 की स्थिति में 0.95 लाख मे.टन यूरिया का स्कंध शेष है। यूरिया की आपूर्ति उपलब्धता अनुसार जिलों को जारी है। यूरिया की वितरण की अव्यवस्था एवं कालाबाजारी को रोकने तथा निर्धारित दर पर ही यूरिया की बिक्री सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं संभाग स्तर पर निरक्षण दल गठित किये गये हैं, जो कि उर्वरक के विक्रय केन्द्रों एवं गोदामों का निरीक्षण कर रहे हैं।

यह सही है कि जबलपुर जिले में दिनांक 19.01.2015 को विपणन संघ के जबलपुर मण्डी विजयनगर स्थित डबललॉक केन्द्र के समक्ष किसानों द्वारा यूरिया खाद नगद वितरण के लिए प्रदर्शन किया एवं मण्डी गेट बन्द कर दिया गया। किन्तु इसके पश्चात कृषि विभाग के अधिकारियों एवं जिला विपणन अधिकारियों के द्वारा कृषकों को समझाईश देकर उपलब्ध यूरिया के आधार पर कृषकों को यूरिया उर्वरक का वितरण किया गया। 19 जनवरी 2015 को कृषि उपज मण्डी स्थित विपणन संघ के केन्द्र में ऐसा कोई भी कृषक नहीं रहा जिसको यूरिया न मिला हो।

आयुक्त, सहकारिता द्वारा दिनांक 19.11.2014 को ग्वालियर, मुरैना, जबलपुर, दतिया, गुना एवं रायसेन के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में उर्वरकों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये इनमें विदिशा एवं भोपाल जिला सम्मिलित नहीं थे। उक्त जिलों की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के अधिकांश सदस्यों के डिफाल्टर होने एवं अन्य स्तरों पर डिफाल्ट होने के कारण समिति स्तर पर उर्वरकों का ऋण एवं नगद में वितरण व्यवस्थित तौर पर नहीं हो पा रहा था। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए डिफाल्टर किसानों को समिति स्तर पर नगद में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया गया था कि नियमित कृषकों को ऋण पर उर्वरक उपलब्ध कराया जावे भले ही उसके क्षेत्र के सहकारी बैंक का अन्य स्तरों पर भी डिफाल्ट हो।

यह कथन सही नहीं है कि खरगोन, बड़वानी एवं झाबुआ जिले में किसानों ने कालाबाजारी से अधिक मूल्य में यूरिया उर्वरक खरीदा है जबकि वास्तविकता यह है कि खरगोन, बड़वानी एवं झाबुआ जिलों में निर्धारित दर पर ही किसानों ने उर्वरक खरीदा है। कालाबाजारी तथा अधिक मूल्य पर यूरिया खरीदने की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

उपलब्धता अनुसार जिलों को उर्वरक उपलब्ध कराया गया है। 2014-15 में दिनांक 01.10.2014 से 31.03.2015 के लिए 25.60 लाख मे.टन उर्वरक भण्डारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके विरुद्ध दिनांक 16.02.2015 तक 22.74 लाख मे.टन उर्वरक का भण्डारण किया जाकर 19.08 लाख मे.टन उर्वरक वितरण किया जा चुका है। प्रदेश में 3.66 लाख मे.टन उर्वरक दिनांक 16.02.2015 की स्थिति में शेष है। उर्वरक की कालाबाजारी रोकने एवं निर्धारित दर पर ही बिक्री सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं संभाग स्तर पर निरीक्षण दल गठित किये गये हैं जो कि उर्वरकों के बिक्री केन्द्र एवं गोदामों का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रदेश में पर्याप्त उर्वरक होने से यूरिया एवं अन्य उर्वरकों की आपूर्ति निरंतर जारी है। अतः किसानों में शासन के प्रति रोष व्याप्त होना नहीं पाया गया।

डॉ.गोविन्द सिंह- अध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है और सरकार से अनुरोध है

कि सच्चाई को स्वीकार करने में परहेज नहीं करना चाहिए. अध्यक्ष जी,आपके जिले हरदा और होशंगाबाद में भारी पैमाने पर जन आन्दोलन हुए हैं और पूरे प्रदेश में भी हुए हैं. पहली बार भिण्ड जिले में 8-8 साल की बच्चियों को किसानों ने खाद के लिए लाईन लगा कर बिठा दिया.सभी समाचार पत्रों में यह बात आई और टी.वी. पर और रेडियों पर समाचार चलते रहे. मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके जैसे बहादुर आदमी को सदन में इस तरह का वक्तव्य नहीं पढ़ना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, दूसरा आपसे अनुरोध है, एक नीति अगर बदल दें तो यह यूरिया का संकट समाप्त किया जा सकता है. माननीय गोपाल भार्गव जी जब पूर्व में कृषि मंत्री थे तब उन्होंने पॉलिसी इन्होंने बदल दी. पहले जो यूरिया का जो स्टॉक होता था उसमें मार्फेड को नोडल एजन्सी बनाया हुआ था और मार्फेड 15 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में हर सोसायटी में यूरिया खाद भर देते थे. और उसके बाद खाद पहुंचा देते थे. मार्फेड के पास पैसा नहीं होता था तो सरकार 4 महीने के लिए बिना ब्याज का ऋण देती थी. 4 महीने के बाद जैसे ही वर्षा चालू हुई, 15 जून के बाद खाद बिकने लगा और सरकार को मार्फेड पैसा वापस करती थी. उस समय एक प्रतिबंध और था कि 80-20 का फर्क था. जो यूरिया के उद्योगपति हैं, जहां यूरिया के कारखाने हैं, उनको केवल 20 प्रतिशत यूरिया व्यापारियों को देने का और 80 प्रतिशत सोसाइटियों को देने का प्रावधान था. परन्तु श्री गोपाल भार्गव जी ने अपने समय में, पता नहीं व्यापारियों से क्या ...

अध्यक्ष महोदय - कृपया अपना प्रश्न करें.

डॉ. गोविन्द सिंह - वह जो 80-20 की पॉलिसी थी, माननीय मंत्री जी पुरानी पॉलिसी जो कांग्रेस के समय में थी, उससे कभी कोई संकट नहीं आता था, जो पॉलिसी आपने समाप्त की थी, क्या आप उसको पुनः प्रारंभ करेंगे?

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि अपनी स्मरण शक्ति को जरा पीछे की तरफ ले जाएं और स्मरण करें.मैंने ही यह तय किया था कि यूरिया शत-प्रतिशत सहकारी समितियों के माध्यम से ही वितरित किया जाएगा, उसके बाद में पॉलिसी में कुछ

बदलाव हुआ है. लेकिन उसके बाद में 50-50 प्रतिशत यह हुआ. 50 प्रतिशत प्राइवेट ट्रेडर्स को और 50 प्रतिशत सोसाइटियों को, इसके बाद में मैंने पहल करके उसको 70-30 प्रतिशत का रेशो करवाया. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे जाकर और कुछ भी जो ज्यादा युक्तियुक्तकरण होगा, जो आवश्यक होगा, वह करेंगे. पहली प्राथमिकता हमारी सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से है और इसके बाद में प्राइवेट व्यापारियों के माध्यम से है.

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके समय में वह व्यवस्था नहीं थी. लेकिन जब मैं पिछले कार्यकाल में सहकारिता मंत्री था, उस समय कृषि विभाग मेरे पास में था. उस समय मैंने 300 करोड़ रुपए की लिमिट राज्य सरकार की ओर से मार्फेड के लिए स्वीकृत कराई थी. आज वह 500 करोड़ रुपए की लिमिट है. इस कारण से मैं यह कह सकता हूं कि पिछले समय जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके समय से जबकि 1 रुपए की भी लिमिट स्वीकृत नहीं हुई थी, हमने 500 करोड़ रुपए की लिमिट मार्फेड के लिए राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृत की है, जिससे कि आज हम खाद्य भण्डारण में सबसे अग्रणी राज्य भारत में हैं.

अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए यह खुशी है कि इस बार जो 2 प्राकृतिक आपदाएं आईं, एक तो पूर्वी क्षेत्र में जो 'हुदहुद' तूफान आया. इस तूफान के कारण भी और पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात के जो पोर्ट कांडला वगैरह थे, यहां पर भी दिक्कत आई, इसके कारण से जो पानी के जहाज थे, जिनसे सब माल आता है, उनसे माल उतारने में विलंब हुआ, यह सारी परेशानी मौसम के कारण हुई. प्राकृतिक आपदा के कारण यह विलंब हुआ. लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश में इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि जिससे बहुत ज्यादा गंभीर समस्या राज्य में हो. जो हमारा बौनी का रकबा है, वह पिछले साल की तुलना में ज्यादा है और हमारा उत्पादन भी आगे आने वाले आंकड़ों में, आने वाला जो उपार्जन है, उसमें आप देखेंगे. आज हमारे मुख्यमंत्री जी 'कृषि कर्मण अवार्ड' लेने के लिए श्रीगंगानगर गये हैं. मैं कहना चाहता हूं

कि चौथे वर्ष भी हमारे लिये यह 'कृषि कर्मण अवार्ड' मिलेगा. (मेजों की थपथपाहट)...क्योंकि हम पूरी तरह से फर्टिलाइजर के मामले में और सीड्स के मामले में भी सावधान हैं.

अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहते हैं कि वर्षवार हमने जितना लक्ष्य रखा था, वह शुरू के दो माह में हमें निश्चित रूप से कम प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद में स्थिति संभल गयी. आज हम बेहतर स्थिति में हैं. हमारे पास में यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है. मैं यह भी सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस बार खरीफ की फसल के लिए 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन हमने सुनिश्चित कर लिया है. 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया पहले से हम स्टोर करके रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में हमारे राज्य के किसानों के ऊपर कोई दिक्कत न आए.

डॉ. गोविन्द सिंह -- अध्यक्ष महोदय हम एक प्रश्न और करना चाहते हैं. नीति के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है उसके लिए धन्यवाद. लेकिन वह 80 और 20 कर दें केवल इतना चाहते हैं. आपके जो सोसायटियों के कई निर्देश हैं कि डिफाल्टर किसानों को नहीं देंगे. लेकिन जो लोग नगद लेना चाहते हैं उस पर रोक लगा देते हैं. हमारा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार का निर्देश जारी हो जाय कि जो किसान डिफाल्टर हैं उनको नगद व्यवस्था में यूरिया खाद उपलब्ध करायी जाय. आपने कहा है कि आप 31 मार्च तक का स्टॉक कर रहे हैं, अब तो गेहूं की खरीदी आ गई है एक कहावत है कि क्या बरसा जब कृषि सुखानी, जब पूरा बर्बाद और चौपट हो गया है तब आप पहुंचा रहे हैं. आपको धन्यवाद की आपने अगले वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, किसान आगे से परेशान नहीं होगा लेकिन अगर पहले से चेत जाया करें तो अच्छा रहेगा. हमारा कहना है आप केवल इतना ही बता दें कि निरीक्षण दल समय समय पर गठित करने के निर्देश दिये हैं उनको करते रहें दूसरा जो डिफाल्टर हैं उनके लिए सोसायटियों को निर्देश जारी करें कि जो किसान डिफाल्टर हैं और वह नगद में यूरिया लेना चाहते हैं तो उनको नगद में यूरिया उपलब्ध कराया जाय.

श्री गोपाल भार्गव -- अध्यक्ष महोदय मैंने अपने उत्तर में ही पढ़ा है कि जिन बैंकों में ज्यादा डिफाल्टर थे और जिन किसानों को पात्रता नहीं थी. वहां पर हमने विशेष सुविधा दी है कि वह किसान सेवा सहकारी समितियों से खाद प्राप्त कर सकता है. जहां भी ऐसी आवश्यकता होगी बैंकों में, सोसायटियों में जिलों में हम किसानों के लिए यह उपलब्ध करायेंगे.

श्री आरिफ अकील -- माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दो बात पूछना चाहता हूं. आपने कहा कि स्टॉक पर्याप्त कर लिया है तो यह जो आपने स्टॉक कर लिया है तो जितनी जिले में आवश्यकता है उस जिले में किसानों को जब आवश्यकता होती है उस समय तक खाद पहुंच जायेगी या ऐसा पता चला कि एक जगह पर इकट्ठा है और जिलेवार जितनी आवश्यकता है वहां पर उतना नहीं पहुंच रहा है. पहला प्रश्न तो यह है और दूसरा यह कि जो डिफाल्टर किसान है उनको खाद नहीं मिल पायी है मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं आप नोट कर लें कि सलामतपुर की जो सोसायटी है उसमें जो लोग डिफाल्टर नहीं थे उनसे भी नगद पैसे लेकर खाद दी है. आपकी जो जीरो प्रतिशत की योजना है उसको समाप्त कर दिया है इसकी आप जांच कर लें. जांच में अगर ऐसा पाया जाय कि जो डिफाल्टर नहीं है लेकिन उनसे भी नगद पैसे लेकर खाद दिया है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करें.

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य को और सदन को यह फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी कृषक चाहे वह डिफाल्टर हो या नहीं हो वह खाद से या बीज से वंचित नहीं रहेगा. इस कारण से कि वह डिफाल्टर है उसके लिए हम नगद में खाद और बीज देने की व्यवस्था करेंगे, चाहे फिर वह रायसेन जिला हो या अन्य कोई भी जिला हो. जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है तो यह भी हम सुनिश्चित कर लेंगे कृषि उत्पादन आयुक्त की बैठक में जो कि 6 माह में बैठक होती है रबी और खरीफ की. उस बैठक में हालांकि यह तय हो जाता है लेकिन हम और सुनिश्चित करेंगे कि पहले से ही कि कहां पर कितनी मांग है और कितनी आवश्यकता है उसकी समय रहते हुए वहां पर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे.

श्री आरिफ अकील -- मैंने प्रश्न में सीधा सीधा प्रश्न में पूछा था कि जो डिफाल्टर नहीं है. उनसे नगद पैसे लेकर खाद दी गई है तो उनकी जांच करा लेंगे क्या.

श्री गोपाल भार्गव -- जी उस सोसायटी की जांच करा लेंगे.

अध्यक्ष महोदय -- आज की कार्यसूची में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाय. मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय मैं तो प्रश्न पूछ लूं मेरा भी नाम है इसमें.

श्री गोपाल भार्गव -- अध्यक्ष महोदय इस पर 139 में पिछले सत्र में चर्चा हो गई है. अब तो बोवनी समाप्त हो गई है कटाई का सीजन आ गया है. अब तो उपार्जन पर चर्चा करें.

श्री रामनिवास रावत -- उपार्जन पर तो आपने बोनस समाप्त कर दिया है.

श्री गोपाल भार्गव -- बोनस देंगे आप चिंता मत करो, किसी न किसी रूप में बोनस मिलेगा

श्री रामनिवास रावत -- यह सरकार की घोषणा है कि गोपाल भार्गव की है.

श्री गोपाल भार्गव -- मैं पूरी जिम्मेदारी से घोषणा कर रहा हूं कि मध्यप्रदेश के किसानों को उनके कृषि उत्पाद का वाजिब हक मध्यप्रदेश की सरकार देश में सबसे अब्बल नंबर पर दिलायेगी. आप चिंता न करें.

श्री रामनिवास रावत -- आपने बोनस की बात की थी आप अपनी बात से पलट गये हैं.

श्री गोपाल भार्गव -- देश में सबसे ज्यादा यदि गेहूं का मूल्य मिलेगा तो मध्यप्रदेश में मिलेगा आप चिंता मत करो. किसी न किसी रूप में हम कम्पनसेट करेंगे.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में भी कहा है कि किसानों का कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ है, न किसानों में रोष और आक्रोश व्याप्त था. यह उत्तर में भी आया है. मंत्री जी ने उत्तर की 6 वीं लाइन में दिया है कि दिनांक 16.2.2015

की स्थिति में 0.95 लाख टन यूरिया का स्कंध शेष है. और अंतिम पैराग्राफ की पांचवी लाईन में दिया हुआ है कि 3.66 लाख मैट्रिक उर्वरक दिनांक 16.2.2015 की स्थिति में शेष है . तो यह यूरिया से संबंधित पूरा ध्यानाकर्षण था इसमें कौन सा उत्तर सही है यह मंत्री जी बता दें. दूसरा प्रदेश में आंदोलन हुये, पूरे प्रदेश में चक्का जाम हुआ, पूरे प्रदेश में थानों से उर्वरक बंटा लेकिन सरकार इसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है, पूरी मीडिया, हम सब लोग सबको असत्य और झुठलाने का काम यह सरकार कर रही है. मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि भारत सरकार से कितना कितना उर्वरक कौन कौन से महीने में कौन कौन सी दिनांक को आपको प्राप्त हुआ और नवम्बर और दिसम्बर में सबसे ज्यादा यूरिया की जरूरत महसूस हुई और इसी कारण इन्होंने जनवरी में पूरा यूरिया भारत सरकार से मंगाया जो इन्हें जनवरी में प्राप्त हुआ यह सरकार की अक्षमता और सरकार की अव्यवस्थित शैली के कारण हुआ तो यह बता दें कि इन्हें कब कब प्राप्त हुआ और जैसा कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा कि जो 80 और 20 का रेश्यो है, 80 सहकारी सोसायटियों को 20 प्रायवेट डीलर्स को देने की व्यवस्था जरूर करें क्योंकि यूरिया जहां 287 का मिलना था वहां साढ़े 500 600 तक में खरीदा गया इसे मंत्री जी स्वीकार नहीं करेंगे और अलग से बात करेंगे तो वही बता देंगे कि क्या करें यार.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया आप प्रश्न तो पूछें. प्रश्न तो इसमें कुछ आपका आया नहीं.

श्री रामनिवास रावत--यही प्रश्न है. भारत सरकार से इनको कब कब किस किस दिनांक को कितना कितना मैट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुआ यह बता दें.

श्री गोपाल भार्गव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से हमें अक्टूबर के माह में डिमांड थी हमारी 2 लाख 85 हजार मैट्रिक टन भारत सरकार का एलोकेशन था 2 लाख 36 हजार 700 मैट्रिक टन, और ट्रांजिट सप्लाई जो हमारी हुई 1 लाख 71 हजार 395 मैट्रिक टन. इसी तरह से नवम्बर 2014 में 4 लाख 24 हजार मैट्रिक टन गवर्मेंट आफ इंडिया का एलोकेशन था 4 लाख 2 हजार 150 मैट्रिक टन और सप्लाई विथ ट्रांजिट थी 3 लाख 10 हजार मैट्रिक टन. दिसम्बर 2014 में

3 लाख 70 हजार मैट्रिक टन हमारी डिमांड थी, और गवर्मेंट आफ इंडिया से हमें 3 लाख 70 हजार मैट्रिक टन का एलोकेशन हुआ और सप्लाई विथ ट्रांजिट 4 लाख 18 हजार 723 मैट्रिक टन थी.

श्री रामनिवास रावत-- क्या आंदोलन नहीं हुये प्रदेश में.

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपको जानकारी दे रहा हूं. जनवरी 2015 में 1 लाख 64 हजार की डिमांड थी 1 लाख 76 हजार का आवंटन हुआ. 2 लाख 5 हजार 321 मैट्रिक टन की सप्लाई हुई. फरवरी में 28 हजार की डिमांड थी 1 लाख 31 हजार का एलाटमेंट हुआ और 79 हजार 211 का ट्रांजिट हुआ. जहां तक आंदोलन की बात है . कहीं कहीं पर किन्हीं किन्हीं जिलों से यह जानकारी आई थी कि जैसा मैंने कहा कि शुरूआती महीने में प्राकृतिक आपदा के कारण सप्लाई में और डिमांड में अंतर रहा और इसी कारण से यह सारे विषय आये थे, लेकिन उन्हें प्रशासन ने और चूंकि मुख्यमंत्री जी ने प्रतिदिन सुबह कम से कम एक घंटे तक यूरिया की समस्या पर राज्य भर में चर्चा करके और भारत सरकार के अधिकारियों से और माननीय अनंत कुमार जी जो फर्टिलाइजर मंत्री थे उनसे प्रतिदिन चर्चा करके यह सुनिश्चित करवाया जो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है मध्यप्रदेश के लिये तो इस कारण से मानकर के चलते हैं कि हमने बहुत कठिन परिस्थितियों में बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाने का काम किया है.

श्री रामनिवास रावत-- भविष्य में, जो ब्लैक मार्केटिंग होती है किसानों को मंहगें दामों पर खरीदना पड़ता है उसको रोकने की क्या व्यवस्था करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- बस अब आपका उत्तर आ गया है.

श्री रामनिवास रावत-- मंत्री जी आत्मा की आवाज से बता दो.

श्री गोपाल भार्गव -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सोसायटियों से सुनिश्चित करेंगे ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर सोसायटियों के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे.

श्री कमलेश्वर पटेल -- चर्चा और समीक्षा डेली हुई है. व्यवस्था अव्यवस्था में फेली हुई है. यूरिया खाद की बहुत समस्या है .

अध्यक्ष महोदय -- कृपया बैठ जाईये. अब नहीं.

(2) इन्दौर एवं उज्जैन संभाग में साइबर अपराधों में वृद्धि होना.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (मंदसौर)- अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

फेसबुक, एवं अन्य इन्टरनेट साधनों के कारण उज्जैन संभाग में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। विद्यालयीन बच्चे भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। इंदौर, उज्जैन संभाग में गत 1 वर्ष में इस तरह के 1400 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुये हैं जिसमें 800 के लगभग छात्र-छात्राओं पर है, पर्याप्त आपराधिक विषयों की जानकारी न होने के कारण ये छात्र छात्राएं कभी धर्म विशेष पर भी टिप्पणी कर देते हैं, जिससे पुलिस की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही के कारण इनका कैरियर चौपट होता जा रहा है। संभाग में इस ओर पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की जागरूकता संबंधी कार्यवाही प्रचलन में नहीं है। साइबर अपराध को लेकर उज्जैन संभाग के विद्यालय एवं महाविद्यालयों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। इस गंभीर विषय को लेकर अभिभावकों में भारी आक्रोश है

1.06 बजे

{उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.}

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) -- उपाध्यक्ष महोदय,

प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत एक वर्ष (2014) में संचार, इंटरनेट संसाधनों के उपयोग करते हुये इंदौर एवं उज्जैन संभाग में आई.टी.एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कुल 213 अपराध पंजीबद्ध हुए तथा 358 आरोपी गिरफ्तार किये गये। उज्जैन संभाग में विभिन्न थानों में आई.टी. एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कुल 72 अपराध पंजीबद्ध हुये हैं। जिसमें 92 आरोपी गिरफ्तार किये गये हैं। इसी प्रकार इन्दौर संभाग के विभिन्न थानों में आई.टी. एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कुल 141 अपराध पंजीबद्ध हुये हैं जिसमें 266 आरोपी गिरफ्तार किये गये हैं। इंदौर संभाग के अपराधिक प्रकरणों में छात्र-छात्राओं की संख्या 23 है। उज्जैन संभाग के अपराधिक प्रकरणों में छात्र-छात्राओं की संख्या 09 है।

राज्य सायबर पुलिस द्वारा स्कूलों एवं महाविद्यालयों में समय-समय पर छात्र छात्राओं को सायबर अपराध संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया जाता है। गत वर्ष में राज्य सायबर पुलिस द्वारा 10 महाविद्यालयों में संगोष्ठियाँ आयोजित की गयीं तथा 08 स्कूलों में सायबर अपराध संबंधित व्याख्यान दिया गया है। सायबर अपराध संबंधी आमजन को जागरूक करने हेतु समय-समय पर समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये आवश्यक जानकारियाँ दी जा रही हैं।

इन्दौर जिले में भी महाविद्यालयीन स्तर पर छात्र/छात्राओं में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सायबर क्राइम तथा अन्य विषयों पर माह जनवरी में आयोजित किया गया है।

अभी हाल (गत माह) ही में जिला देवास में पुलिस द्वारा छात्र-छात्राओं हेतु एक जनजागरण कार्यक्रम, बदलते परिवेश में सायबर क्राइम के संबंध में आवश्यक सावधानी बरते विषयक, आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग बारह सौ छात्र-छात्राओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गयी।

इसी प्रकार से उज्जैन संभाग के अन्य जिलों में भी सायबर अपराधों के प्रति युवाओं में जागरूकता हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है तथा भविष्य में भी पुलिस द्वारा संवेदनशील विषय पर सतत जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन किया जावेगा।

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा,

विषय बड़ा गंभीर है. कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, किन्तु वर्तमान

मोबाइल युग में इसके लगातार दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं. मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री

जी का ध्यान आकर्षित भी करूंगा और उनसे अपेक्षा भी करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर वे अपने विभाग में और अधिक कसावट लाते हुए न्याय प्रदान करें। मंत्री जी ने शासन के उत्तर में इस बात को उल्लेखित भी किया है कि एक वर्ष में 426 प्रकरण इन्दौर-उज्जैन संभाग में पंजीबद्ध हुए हैं। जिसके बदले में 778 छात्र/छात्राओं की, अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मंत्री जी ने मेरे ध्यानाकर्षण के उत्तर में यह भी स्वीकार किया है कि कुल 18 विद्यालय एवं महाविद्यालयों में व्याख्यान हुए हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर। मेरा मंत्री जी से प्रश्न यह है, मैं मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि साइबर क्राइम को लेकर के एक नये अपराध का सूत्रपात, पैदा, प्रारंभ हुआ है। चिंता स्वाभाविक है। मैं मंत्री जी से इस बात को लेकर के यह जानना चाहूंगा कि फेस बुक, वाट्स एप और इन्टरनेट के इस दुरुपयोग को रोकने को लेकर के या जो फर्जी फेस बुक की आई.डीज़ बन रही है, छात्र-छात्राओं के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं, क्या आपके विभाग में इन क्राइम्स को रोकने के लिये संसाधनों की वृद्धि की जायेगी या अभी वर्तमान में सिर्फ भोपाल में और एक इन्दौर में आपका रेंज की जो व्यवस्था है जोनल के माध्यम से, क्या इसको बढ़ाते हुए उज्जैन में, ग्वालियर में, जबलपुर में वहां भी इस प्रकार से आप संसाधनों से सुसज्जित करेंगे और आपके विभाग के वे अधिकारी, जो स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हैं, उनको समय दर समय इस बात की व्यवस्था दी जाती है कि इस काम के साथ-साथ आप ये काम भी करें, तो साइबर का काम कर तो रहे हैं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के उन अधिकारियों को प्रशिक्षित ढ़करते हुए इनकी संख्या भी बढ़ाई जायेगी , रेंज भी बढ़ाये जायेंगे ?

श्री बाबूलाल गौर--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा है और मैं इनका बहुत ही आभारी हूं और बहुत आभारी इसलिये हूं कि यह जिस प्रकार के साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, उसके लिये हम प्रशिक्षित अधिकारियों को भी और कर्मचारियों को भी और केन्द्र को भी बढ़ावेंगे।

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है कि बड़ी संख्या इन्दौर, उज्जैन संभाग में महाविद्यालयों की विद्यालयों की है और अभी कुल मिला कर 18 स्थानों पर व्याख्यानों की संख्या...

उपाध्यक्ष महोदय--आप भूमिका तो लंबी बना चुके हैं, अब सीधे प्रश्न पूछ लें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--क्या व्याख्यानों की संख्या विद्यालय और महाविद्यालयों में बढ़ायेगे ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपके द्वारा व्याख्यानों की जो संख्या आई है, तो क्या व्याख्यानों की वह संख्या विद्यालय और महाविद्यालयों में बढ़ायेगे ? मात्र 18 स्थानों पर विद्यालय और महाविद्यालयों में व्याख्यानों की व्यवस्था की गई है, जबकि विद्यालय और महाविद्यालयों की संख्या असंख्य है, बड़ी मात्रा में है.

उपाध्यक्ष महोदय--माननीय मंत्री जी, आप वह बढ़ायेगे क्या ?

श्री बाबूलाल गैर गौर --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न महत्वपूर्ण है और अभी आपने कहा कि प्रशिक्षित अधिकारी होना चाहिये, तो अब प्रशिक्षित अधिकारी होने के बाद जैसा यह चाह रहे हैं, वैसा करेंगे. भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर में साइबर थाने भी खोले जायेंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--एक और निवेदन है.

उपाध्यक्ष महोदय--सिसोदिया जी, गौर साहब ने काफी कुछ कह दिया है उन्होंने 4 जगह नये केन्द्र खोलने की बात कह दी है, तो आपका जवाब आ गया है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार--उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह कहा है कि जैसा यह चाहते हैं, वैसा ही करेंगे, मतलब साल-दो साल चाहते रहो और करवाते रहो, आपको ऐसा जवाब क्या कहीं मिलेगा ? यदि आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अब आप अपने आपको कम कर रहे हैं

उपाध्यक्ष महोदय--अब आगे प्रश्न पूछने की तो जरूरत ही नहीं बची ना, अब तो खतम हो गई बात. यशपाल जी, अब तो कुछ बचा ही नहीं, माननीय मंत्री जी ने सब कुछ वायदा कर दिया.

श्री बाला बच्चन--माननीय यशपाल जी, अब तो आपको यह तय करना है कि क्या चाहना है आगे.

उपाध्यक्ष महोदय--अब आप बैठ जायें यशपाल जी, आपने कई प्रश्न कर लिये. आगे बढ़ने दें.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार--अबकी बार मंत्री जी यह कहेंगे कि विपक्ष के लोग जो चाहेंगे, मैं वह भी कर दूंगा.

उपाध्यक्ष महोदय--यह गौर साहब की महानता है .

डॉ. गौरीशंकर शेजवार--देखिये, अब मंत्री जी आज बहुत उदार हैं, आप जो चाहे वह पूछ लो, लेकिन अपनी सीमाओं को स्वयं मत कम करियेगा.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय--अब सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ने दें.

श्री देवेन्द्र वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं, मेरा निवेदन है कि पिछले वर्ष हमारे खंडवा में फेस बुक पर गलत फोटो डालने के कारण लगभग 10 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा और 2 लोगों की उसमें हत्या हो गई, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से कोई नया व्यक्ति फेस बुक या व्हाट्स ऐप पर अपना एकाउंट शुरू करता है, तो वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, अगर उस प्रकार का रजिस्ट्रेशन प्रशासन द्वारा कराया जाये, तो प्रशासन को व्हाट्स ऐप या फेस बुक पर डिपेन्ड नहीं होना पड़ेगा.

उपाध्यक्ष महोदय--माननीय मंत्री जी जवाब दें, पर क्या यह ह तकनीकी रूप से संभव है कि नहीं ?

श्री बाबूलाल गौर--जब तक कोई शिकायत ना हो, संभव नहीं है.

उपाध्यक्ष महोदय--जी, जवाब पूरी तरह से मुकम्मल है.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पंचम् प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री गोपीलाल जाटव:-
सभापति

अध्यक्ष महोदय, मैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पों संबंधी समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ:-
प्रतिवेदन इस प्रकार है:-
शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2015को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प

शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2015

निर्धारित समय

1 (क्रमांक-2)	श्री संजय पाठक	20 मिनट
2 (क्रमांक-4)	श्री यशपाल सिंह सिसौदिया	20 मिनट
3 (क्रमांक-8)	श्री रामलल्लू बैस	20 मिनट
4 (क्रमांक-18)	डॉ. मोहन यादव	45 मिनट
5 (क्रमांक-20)	श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा	45 मिनट

श्री गोपीलाल जाटव:-
सभापति

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पंचम् प्रतिवेदन से सहमत है।

उपाध्यक्ष महोदय—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

प्रश्न यह है कि:-

सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के

पंचम् प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सभापति तालिका

अध्यक्ष महोदय :- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 9 के उपनियम(1) के अधीन, मैं, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूँ :-

1. श्री मानवेन्द्र सिंह,
2. श्री कैलाश चावला,
3. श्रीमती अर्चना चिटनीस,
4. श्री गिरीश गौतम ,
5. श्री रामनिवास रावत, तथा
6. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा .

अध्यक्षीय घोषणा

माननीय उपाध्यक्ष—मध्यप्रदेश के विभिन्न संस्थानों के उत्पादों के विक्रय केन्द्रों का संचालन वर्तमान सत्र की अवधि में प्रातः 09.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक विधान सभा परिसर में कैंटीन गेट के समक्ष किया जायेगा.

इन विक्रय केन्द्रों का शुभारंभ आज सदन की बैठक स्थगित होने के उपरांत होगा.

सभी माननीय सदस्यों की इस अवसर पर उपस्थिति अपेक्षित है.

विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2015 को प्रातः 10.30 बजे तक के लिये स्थगित.

अपराह्न 1 बजकर 17 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2015 (1 फाल्गुन, शक संवत् 1936) के प्रातः 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी

भोपाल,

प्रमुख सचिव,

दिनांक: 19 फरवरी, 2015

मध्यप्रदेश विधान सभा